



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941

No. 327]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पैरासिटामोल" के आयातों के संबंध में तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच (एस एस आर)।

1. **फा.सं. 7/16/2018 – डी जी ए डी :** 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
2. अतः संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 30 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000 - डी जी ए डी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा 16 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000 - डी जी ए डी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 89/2001-सीमा-शुल्क दिनांक 6 सितम्बर, 2001 द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 60/1/2000 - डी जी ए डी दिनांक 22 जनवरी, 2002 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 29/2002-सीमा शुल्क दिनांक 27 मार्च, 2002 के द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से

निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। पहली निर्णायक समीक्षा सम्पन्न हुई और प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/20/2006 - डी जी ए डी दिनांक 23 जुलाई, 2007 द्वारा निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम जारी किए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं 99/2007-सीमा शुल्क दिनांक 3 सितम्बर, 2007 द्वारा नियत शुल्क लगाया गया था। दूसरी निर्णायक समीक्षा सम्पन्न हुई और प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/1009/2012 - डी जी ए डी दिनांक 26 अगस्त, 2013 द्वारा निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम जारी किए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं 26/2013-सीमा शुल्क दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा नियत शुल्क लगाया गया था। एक तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच 24 मई, 2018 को आरंभ की गई थी और अंतिम जांच परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.2019 की अधिसूचना संख्या 7/16/2018 - डी जी ए डी के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से पैरासिटामोल के आयातों पर लगाई गई मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी न रखने की सिफारिश की थी। उसके बाद, विशेष सिविल आवेदन संख्या 2019 का 5278 गुजरात उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीसरे निर्णायक समीक्षा जांच में क्रमशः 29.01.2019 और 15.01.2019 को जारी किये गये संदिग्ध अंतिम जांच परिणामों और प्रकटन विवरण को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 3 जुलाई, 2019 के अपने निर्णय में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार हेतु इस मामले को वापस लिये जाने का आदेश दिया।

3. अतः नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार यदि शुल्क की समाप्ति से पहले शुरू की गई समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है।
4. और उक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपाय के समाप्त होने की तारीख से पहले तर्कसंगत समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
5. अतः, समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए यह याचिका मै. फार्मसन फार्मास्टीकल गुजरात प्रा. लि. और मै. श्री कृष्णा फार्मास्टीकल लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है और मै. भारत कैमिकल्स, मै. ग्रेन्युल्स इंडिया लि. और मै. मेघमनी यूनिकैम एल एल पी द्वारा समर्थित है और इसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य सहित विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 मई, 2018 की अधिसूचना सं. फा. सं. 7/16/2018 - डी जी ए डी जारी की जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की गई। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 39/2018-सीमा शुल्क दिनांक 20 अगस्त, 2018 के माध्यम से 24 मई, 2019 तक बढ़ा दिया गया है। जिसे बाद में दिनांक 12 जुलाई, 2019 के अधिसूचना सं. 27/2019 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से 27 अक्टूबर, 2019 तक बढ़ाया गया था।
7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जाँचों के सभी पहलू शामिल हैं।

क. सामान्य प्रक्रिया

8. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- i. प्राधिकारी के संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्यवाही करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 मई, 2018 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें चीन जन. गण. के मूल की और वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की गई।
- iii. प्राधिकारी ने नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादक/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की तारीख के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को उपलब्ध कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई।
- v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों (जिनके व्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावली भेजी और उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

- क) अनहुई बेई कैमिकल इंडस्ट्री कं लिमिटेड
- ख) अनहुई फुबोर फार्मास्टीकल
- ग) झेजियांग कंगले फार्मास्टीकल कंपनी
- घ) मैसर्स वानजाउ फार्मास्टीकल फैक्ट्री
- ङ) चांगशु हुआगांग फार्मास्टीकल कंपनी लिमिटेड
- च) हेबै जियांग गुप कंपनी लिमिटेड
- छ) जिआंगसु वर्ल्ड काइंडली फार्मास्टीकल लिमि.
- ज) जिआंगसु गुओहेंग फार्मा कैमिकल कंपनी लिमिटेड
- झ) शंघाई बाइलियन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- ञ) लियोनयुआन सिटी बैयांग फार्मास्टीकल
- ट) रनकी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- ठ) अनिकुलु वन फार्मास्टीकल कं. लि

vi. निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क) मेसर्स अंकिउ लू एन फार्मास्टीकल कं, लिमिटेड
- ख) मेसर्स ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं, लिमिटेड
- ग) चीन सिनोपार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
- घ) झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

- ड) लियानयुनगांग कंगले फार्मास्टीकल कं, लिमिटेड
- च) झेजियांग कंगले फार्मास्टीकल कं, लिमिटेड
- छ) हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्टीकल कंपनी लिमिटेड
- vii. चीन जन. गण. में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण के दूतावास को पूरक प्रश्नावली भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रस्तुत कर दें।
- viii. तथापि किसी भी निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को आयातक प्रश्नावली के साथ जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें प्राधिकारी को विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी:-
- क) औरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड
- ख) शालिना लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
- ग) मेडिकामेन बायोटेक लिमि.
- घ) एडकाँक इनग्राम लिमि.
- ड) सनोफी इंडिया लिमिटेड
- च) फोरट्रेट्स (इंडिया) लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- छ) इंडोको रेमेडीज लिमि.
- ज) एस्ट्रा लाइफकेयर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
- झ) जे. बी. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि.
- ञ) यूनीलिक फार्मा प्रा. लिमिटेड
- ट) मेडोफार्म
- ठ) मिलान लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
- ड) एगोग फार्मा लिमिटेड
- ढ) कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड
- x. तथापि संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
- xi. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।
- xii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराएं और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक फाईल के रूप में रखा गया था।
- xiii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत ज्ञात करने के लिए अनुबंध III में

निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2014 - मार्च 2015, अप्रैल 2015 - मार्च 2016, अप्रैल, 2016 - मार्च 2017 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल है।
- xv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों से अतिरिक्त सूचना आवश्यक समझी गई सीमा तक मांगी गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आकड़ों के सत्यापन आवश्यक रूप से अपेक्षित सीमा तक किया गया था।
- xvi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी सिस्टम्स से सौदा-वार आकड़े मंगाए गए थे। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों और सहयोगी निर्यातकों के आकड़ों पर भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य के परिकलन के लिए भरोसा किया है।
- xvii. नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 29 अगस्त, 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इस सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाले हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। हितबद्ध पक्षों को विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत विचारों के खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर उचित ढंग से विचार किया है।
मामले को वापस लिये जाने के बाद दिनांक 19 अगस्त, 2019 को मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी और तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित अनुरोध और प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये थे जिन पर प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया था।
- xviii. ऐसे निर्यातक, उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्ष जिन्होंने प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रस्तुत की है को असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है।
- xix. इस दस्तावेज में *** गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xx. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 65.33 रुपया के रूप में लिया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

ख. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. वर्तमान जांच के अधीन विचाराधीन उत्पाद का दायरे में 'पैरासिटामोल है जिसे एसिटैमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है' है जैसा पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित है। पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है और इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2922.2933 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- ii. पैरासिटामोल एक सफेद पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र $C_8H_9NO_2$ है। पैरासिटामोल एक सामान्य एनाल्जेसिक और एंटीपीयरेटिक दवा है जिसका उपयोग बुखार, सिरदर्द और अन्य मामूली दर्द और पीड़ा से राहत के लिए किया जाता है। यह कई सर्दी और फ्लू की दवाओं और कई लिखी गई दर्द निवारक में एक प्रमुख घटक है।

- iii. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी द्वारा पहले यथा अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू है इसलिए प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान जांच में पीयूसी का दायरा पूर्ववर्ती जांचों के समान ही रहेगा।

ख. 2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

10. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ख. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष सं. 2922.2933 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

12. पूर्ववर्ती जांचों में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है :-

‘मूल तथा पहली एस एस आर जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित ‘पैरासिटामोल है जिसे एसिटेमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है’ चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए इस जांच में मूल जांच तथा पहली एस एस आर जांच में शामिल उत्पाद शामिल है।’

13. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी द्वारा पहले यथा अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू है इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में पी यू सी का दायरा पूर्ववर्ती जांचों के समान ही रहेगा। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

14. अतः प्राधिकारी ने पी यू सी को निम्नानुसार माना है :-

‘पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित ‘पैरासिटामोल है जिसे एसिटेमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है’ चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद शामिल है।’

“पैरासिटामोल एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र $C_8H_9NO_2$ है। पैरासिटामोल एक बल्क भेषज सक्रिय घटक है, जो एनाल्जेसिक और एंटीपीयरेटिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग आरएक्स और ओटीसी दवा के कई प्रकारों में पाउडर, दानों, इंजेक्टिबल्स और गोलियों के रूप में किया जाता है। पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है और इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 2922.2933 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण, केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।”

ग. समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में मापदंडों जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन और टैरिफ वर्गीकरण आदि की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

ग. 2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

16. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों पर प्रश्न नहीं उठाया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित

उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की थी जिस पर आवश्यक संशोधनों के साथ वर्तमान समीक्षा में भी भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु, पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (घ) के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए याचिका मेसर्स फरम्सन फार्मास्यूटिकल्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्टिकल लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मै. भारत केमिकल्स, मेसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, और मेसर्स मेघमनी एलएलपी द्वारा समर्थित है।
- ii. मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्टिकल के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद को आयात नहीं किया है। मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्टिकल लिमिटेड ने केवल 30 मीट्रिक टन का आयात किया है, जो इसके उत्पादन, भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में बहुत मामूली है।
- iii. याचिकाकर्ता भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा रखते हैं और तदनुसार नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" का गठन करते हैं।
- iv. याचिकाकर्ता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अधीन एक पात्र घरेलू उद्योग है।

घ. 2 निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

19. हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. पाटनरोधी शुल्क की लेवी पाटन मार्जिन पर निर्भर करती है और पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा देने का कोई सिद्धांत नहीं है।
- ii. प्राधिकारी के समक्ष जांच के अधीन उत्पाद से संबंधित सभी चार जांचों में घरेलू उद्योग की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं हुए हैं जिन्हें निम्नानुसार देखा जा सकता है: -
 - क) मूल जांच: यह देखा जा सकता है कि प्राधिकारी के समक्ष मूल जांच में चार उत्पादक थे अर्थात् मेसर्स ट्राइटन लेबोरेटरीज लिमिटेड, मेसर्स वामसी लैब्स लिमिटेड, श्रीनिवास एग्रो इंडस्ट्रीज एंड ड्रग्स लिमिटेड और श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लि. जिन्होंने जांच में भाग लिया और क्षति संबंधी जानकारी दी।
 - ख) पहली निर्णायक समीक्षा: पहली निर्णायक समीक्षा में तीन उत्पादकों के नाम थे, श्री कृष्ण फार्मास्टिकल, मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भारत केमिकल्स लि.।
 - ग) दूसरी निर्णायक समीक्षा: दूसरी एसएसआर में, श्री कृष्णा फार्मास्टिकल लिमिटेड और मेसर्स भारत केमिकल्स लिमिटेड ने क्षति संबंधी जानकारी दी।
 - घ) तीसरी निर्णायक समीक्षा - वर्तमान जांच : वर्तमान जांच में, पुनः केवल 2 उत्पादकों जैसे कि श्री कृष्णा फार्मास्टिकल लिमिटेड और मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्रा. लिमिटेड ने भाग लिया है और क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की है।

- ड) घरेलू उद्योग या घरेलू उत्पादकों का गठन सभी चार जाँचों में अलग-अलग हैं और यह मानना मुश्किल नहीं है कि घरेलू उत्पादकों का गठन उनकी इच्छा पर और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बदल दिया गया था,
- च) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उत्पादक जो पिछली जाँच अर्थात् मूल जाँच और दो निर्णायक समीक्षा जाँचों में याचिकाकर्ता थे, ने वर्तमान मामले में कोई जानकारी नहीं दी है।
- छ) याचिका में कोई विश्लेषण या कारण नहीं है कि वे उत्पादक, जो पहले की जाँच में याचिकाकर्ता थे, वर्तमान जाँच में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं।
- ज) जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में भी, उन उत्पादकों के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है जो जानकारी नहीं दे रहे हैं।
- झ) मेसर्स ट्राइटन लेबोरेटरीज लिमिटेड का वर्ष 1998 में ग्रेनुल्स इंडिया लि. के साथ विलय कर दिया गया था। तथापि, मै. ट्राइटन लेबोरेटरीज लि. को इस तथ्य के बावजूद ग्रेनुल्स इंडिया लि. से एक अलग कंपनी के रूप में पेश किया गया था, कि 30 जनवरी 2001 को मूल जाँच की शुरूआत के समय इन दोनों का विलय हो गया था और मूल जाँच की शुरूआत के समय ट्राइटन लेबोरेटरीज के नाम वाली कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। हालांकि, मूल जाँच के समय घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने वाले घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकारी को गुमराह किया और मूल जाँच में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके पाटनरोधी शुल्क लगवाया था।
- ञ) पहली निर्णायक समीक्षा में मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड को एक आयातक के रूप में दिखाया गया था और जाँच में शामिल नहीं किया गया था। मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। पीओआई में इसकी बिक्री 579 करोड़ रुपये की रही है।
- ट) घरेलू उद्योग ने बावजूद इसके वह सबसे बड़ी कंपनी है, मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड को हुई क्षति की जानकारी नहीं दी है।
- ठ) पिछली दो निर्णायक समीक्षा जाँच में भी, उन जाँचों में सार्थक विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड से क्षति संबंधी कोई भी जानकारी नहीं ली गई थी। याचिका में या जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि वर्तमान जाँच में इस उत्पादक ने जानकारी क्यों नहीं दी है जबकि ग्रेन्यूल्स इंडिया की समामेलित कंपनी अर्थात् ट्राइटन लेबोरेटरीज ने मूल जाँच में एक याचिकाकर्ता के रूप में भाग लिया और क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की।
- iii. मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्रा. लिमिटेड भी भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह पहली निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता था और दूसरी निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता नहीं था। इस उत्पादक के संबंध में भी, याचिका में या जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस उत्पादक ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा में जानकारी क्यों नहीं दी है और अब वर्तमान जाँच में क्षति संबंधी सूचना प्रदान कर रहा है।
- iv. उत्पादन में अधिकांश हिस्सा रखने वाले उत्पादक जो पिछली जाँच में याचिकाकर्ता थे, ने वर्तमान जाँच में क्षति संबंधी जानकारी प्रदान नहीं की है और कुल घरेलू उत्पादन में सीमित और कम हिस्सेदारी वाले उत्पादकों ने ही क्षति संबंधी जानकारी दी है, वर्तमान जाँच में शुल्कों को जारी रखे जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्रत्येक जाँच में घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी काफी सूचना को जाँच से बाहर रखा गया है।
- v. वर्तमान मामला जाँच को समाप्त किए जाने और शुल्कों को हटाये जाने का उपयुक्त मामला है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. यह याचिका मेसर्स फरम्सन फार्मास्टीकल गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्टीकल लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मेसर्स भारत केमिकल्स, मेसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड और मेसर्स मेघमनी एलएलपी द्वारा समर्थित है। जांच की शुरुआत के बाद, एक समर्थक कंपनी अर्थात् मेसर्स भारत केमिकल्स ने समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान की है। तथापि प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया है क्योंकि इसे जांच के अंतिम समय में प्रस्तुत किया गया था।

22. वर्तमान मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत उत्पादकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में निर्धारित कानूनी अपेक्षा पूरी होती है। तथापि, निर्णायक समीक्षा के मामले में मूल जांच में घरेलू उद्योग का गठन एक जैसा होना बांछनीय होता है।

23. प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं में मै. श्री कृष्णा फार्मास्टीकल लिमिटेड ने पी ओ आई के दौरान केवल 30 मीट्रिक टन पी यू सी का आयात किया है, जो कि इसके उत्पादन के संबंध में 0.45% है और भारतीय मांग में 0.06% है, जो बहुत ही मामूली है और इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत करते हुए उन्हें एक पात्र घरेलू उद्योग माना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मौके पर एक दौरे के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की पर्याप्तता और सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता न तो भारत में किसी आयातक से और न ही संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक से संबंधित हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन "कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा" बनता है और इसलिए, नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के अधीन संबद्ध वस्तुओं के योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ङ गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**ङ 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

24. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. निर्यातकों/ उत्पादकों ने गोपनीयता के प्रति अनावश्यक दावे किए हैं अथवा अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है जिसने दायर किए गए उत्तरों के संबंध में अर्थपूर्ण टिप्पणियां करने में घरेलू उद्योग को असमर्थ बनाया। उत्तरों को सही रूप से सूचीबद्ध अथवा संक्षेपीकरण नहीं किया गया है।
- ii. अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराई गई सूचना समझ से परे है। एन सी वी ने आंकड़ों की स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध नहीं की है और इसी कारण से घरेलू उद्योग उस पर विस्तृत टिप्पणियां उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
- iii. प्रश्नावली उत्तरों का अगोपनीय पाठ सकल रूप से अपर्याप्त और अपूर्ण हैं। संबंधित हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी सारी सूचना को प्रकट नहीं किया है जिसे वे नियमों और इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अंतर्गत प्रकट करने के लिए बाधित हैं।

च. 2 निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. याचिकाकर्ताओं ने सीमा शुल्क और टैरिफ नियमावली, 1995 के नियम 7 के उल्लंघन में तर्कसंगत कारणों को उपलब्ध कराए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में निम्नलिखित सूचना को प्रकट नहीं किया है :-
- ख. डी जी सी आई एंड एस से सौदावार और छांटे गए आयात आंकड़े, कच्ची सामग्री /मूल आयात संबंधी आंकड़े और शामिल न किए गए सौदों की सूची को एक्सेल फाइल में सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ग. पूर्ण पी ओ आई के आयात आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और केवल 9 महीनों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
- घ. निर्मित सामान्य मूल्य के मद-वार विवरणों को गोपनीय रखा गया है।
- ङ. याचिकाकर्ताओं, समर्थक उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के कंपनीवार उत्पादन विवरणों को गोपनीय रखा गया है।
- च. पी ओ आई और पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। घरेलू उद्योग ने सिर्फ यह कहा है कि इसे याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तथापि, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट पर कोई वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
- छ. आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्णा फार्मास्युटीकल लिमि. ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- ज. घरेलू उद्योग ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन और वैट समायोजन के लिए निर्यात कीमत से समायोजन का दावा किया है। तथापि, उनके द्वारा उक्त समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- झ. प्रतिशतांक शर्तों में लाभ/ हानि और आर ओ सी ई को गोपनीय रखा गया है।
- ट. माननीय प्राधिकारी कृपया याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त सूचना को प्रकट करने और उसे उपलब्ध कराने का निर्देश दें ताकि निर्यातक/उत्पादक इस जांच में प्रभावी टिप्पणियां करने में सक्षम हो सकें।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता संबंधी बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

“7. गोपनीय सूचना :-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसके सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना की अवज्ञा कर सकते हैं।

27. गोपनीयता के संबंध में संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की जांच की गई है और तदनुसार उनका उल्लेख किया गया है। हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की उसे गोपनीय माने जाने की आवश्यकता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के

गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को अन्य हितवद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. उत्तर दायर करने वाले निर्यातक/ उत्पादकों अर्थात् मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लिमि., झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि., मै. ए एच ए इंटरनेशनल कं. लि., झेजियांग कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली स्वरूप में अपूर्ण है और इन में से किसी ने भी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (भाग-2) दायर नहीं किया है, जिसमें निर्यातकों से उनकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, सौदावार तीसरे देश को निर्यात, घरेलू विक्रियों, मालसूची आदि से संबंधित सूचना की मांग की गई है। ये विवरण/सूचना निर्यातकों के संभावित व्यवहार की संकेतक है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा उन्हें निर्णायक समीक्षा जांच में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अपूर्ण सूचना का मामला नहीं है बल्कि निर्धारित फॉर्मेट में अपेक्षित सूचना दायर करने में पूर्ण असमर्थता का है।
29. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विश्वव्यापी रूप से काफी सीमित है। चूंकि विश्वव्यापी उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत भाग केवल भारत और चीन में होता है जिसमें से उत्पादन का 62 प्रतिशत भाग केवल चीन में होता है जबकि भारत का बाकी 24 प्रतिशत पर अधिकार है। अतः इस उद्योग में किसी प्रकार की रूग्णता भारतीय प्रयोक्ताओं को चीनी उत्पादकों की दया और एकाधिकार के अधीन रखती है।
30. यह कि शुल्क के अपर्याप्त रूप के विपरीत प्रभाव के कारण, देश में बड़े स्तर पर उत्पादन निलंबित था, जो प्रारंभ में पिछले दो दशकों में मौजूद था (ये सभी समापन 5 वर्षों से अधिक पुराने हैं और एडीडी के पिछले विस्तार से पहले के हैं)।
31. वाणिज्य पर 145वीं संसदीय स्थायी समिति जिसने भारतीय उद्योग पर चीनी वस्तुओं के प्रभाव का आकलन किया था, के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ए पी आई क्षेत्र को आयात से संरक्षण की जरूरत है और भारत सरकार भी भारत में एपीआई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है।
32. एक्टिव फार्मास्युटीकल इंग्रीडिएंट्स (ए पी आई) पर दिनांक 24 सितंबर, 2015 की कटोच समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय साथ ही अन्य विनियामक प्राधिकरणों को सम्मिलित कर ए पी आई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक दीर्घावधिक कार्यनीति की आवश्यकता है जिसमें पाटनरोधी जैसे उपायों के विवेकपूर्ण और प्रचुर प्रयोग शामिल हैं।
33. “भारतीय फार्मा के लिए पद्धतियों और अवसरों” पर फरवरी, 2018 संस्करण की फिक्की रिपोर्ट में इस बात पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है कि एपीआई आपूर्तियों के लिए चीन पर निर्भरता फार्मा उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति के विघटनों और कीमत अस्थिरता को प्रकट करती है।
34. भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटीकल विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय जापन के अनुसार देश में ए पी आई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक कृत्तिक बल का गठन किया गया है क्योंकि फार्मास्युटीकल क्षेत्र में अवसरों को लाने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।
35. बड़े पैमाने पर जनता को एक विनियामक तंत्र के जरिए भली भांति संरक्षित किया गया है क्योंकि पैरासिटामोल को औषधि नीति, 2015 में अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची के तहत शामिल किया गया है।
36. पैरासिटामोल देश में उपलब्ध सबसे सस्ती एपीआई में से एक है।

च. 2 निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितवद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी कोई अनुरोध नहीं किया है।

छ. 3 मामले को वापस लिये जाने के बाद घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा अनुरोध किये गये थे।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बार बार किये गये अनुरोधों को संक्षिप्तता के वास्ते नहीं दोहराया गया है।

क) घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

38. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अधिकांश निर्यातों के संबंध में पूर्व की जांच परिणामों में, याचिकाकर्ताओं और विरोधी पक्षकारों दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस अवधि में संबद्ध देशों से निर्यात केवल अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत हुआ है।
39. भारत में निर्यात शुल्क छूट योजना के अंतर्गत हुआ है, आयातकों ने न तो पाटनरोधी शुल्क और न ही मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया है। चूंकि, इन आयातों पर कोई कर और शुल्क भुगतान के योग्य नहीं था। इस कारण से भारतीय सीमा शुल्क को सूचित की गई कीमत असामान्य रूप से अधिक थी क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक कीमत बताने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।
40. चूंकि यह आयात शुल्क छूट योजना के अंतर्गत हुआ है, घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि उस अवधि के दौरान भारतीय सीमा शुल्क को सूचित की गई निर्यात कीमत विश्वास किये जाने लायक नहीं है। इस कारण से घरेलू उद्योग प्राधिकारी से उस कीमत पर विचार करने का अनुरोध करते हैं जिस पर इस सामग्री को इन उत्पादकों द्वारा घरेलू बाजार में असंबंधित व्यापारियों को बेचा गया था।
41. इसके अलावा घरेलू उद्योग यह अनुरोध करते हैं कि शुल्क छूट श्रेणी के अंतर्गत वर्तमान निर्यात यह सिद्ध करता है कि ये वास्तविक कीमत नहीं हैं, जिन पर चीन के उत्पादक इस उत्पाद का निर्यात करेंगे। यह तीसरे देशों की अपेक्षाकृत कम कीमतें हैं जो भारतीय बाजार के लिये निर्यातक की वास्तविक कीमतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
42. इन निर्यातकों के व्यवहार में अंतिम जांच परिणाम के जारी किये जाने के बाद बदलाव आया है। जब इस आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त भी नहीं किया था तब चीन के उत्पादकों और भारतीय निर्यातकों ने बहुत अधिक कम कीमतों पर उत्पादों की बहुत अधिक मात्रा में आयातों का सहारा लिया।
43. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) का उत्पादन वैश्विक रूप से बहुत सीमित है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत चीन और भारत में है जिसमें से चीन और भारत का हिस्सा क्रमशः 62 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है और इस उद्योग में किसी रुग्णता के कारण वैश्विक मांग केवल चीन के उत्पादकों की दया और एकाधिकार पर निर्भर रह जायेगा।
44. इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्यातक की प्रश्नावली का अवलोकन यह सिद्ध करता है कि शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह उल्लेख करता है कि निर्यातक की क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है जिससे निष्क्रिय क्षमता में वृद्धि हुई है। निर्यातक की घरेलू बिक्री में कमी आई है और भारत को बिक्री में वृद्धि हुई है। ये निर्यातक अपने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री 107.71 सी एन वाई प्रति कि. ग्रा. की दर से कर रहे हैं और वे उस उत्पाद की बिक्री भारत में 88.18 सी एन वाई प्रति कि. ग्रा. की दर से कर रहे हैं जो पाटन को दर्शाता है।
45. क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि इन आयातों में पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। आयात की पहुंच कीमत संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत से कम है और इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। शुल्क को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को हानि उठानी पड़ेगी और नियोजित पूंजी पर इसका लाभ नकारात्मक हो जायेगा।
46. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि वे क्षति के फिर से होने की संभावना के आधारों पर शुल्क के विस्तार की मांग कर रहे हैं।
47. सकारात्मक पाटन मार्जिन और कम कीमत पर बिक्री के बावजूद, भारत अन्य बाजारों की तुलना में एक बहुत अधिक कीमत आकर्षक बाजार है।
48. चीन के उत्पादक यह मानते हैं कि इस उत्पाद के लिये उनकी घरेलू खपत में कमी आई है। इन क्षमताओं को उसी अनुपात में कम नहीं किया गया है और इस प्रकार से चीन के बाहर इस उद्योग को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
49. वाणिज्य संबंधी 145वीं संसदीय स्थायी समिति जिसने भारतीय उद्योग पर चीन के सामानों के प्रभाव का आकलन किया है के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ए पी आई क्षेत्र को आयात से संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है और भारत की सरकार भी भारत में ए पी आई क्षेत्र को फिर से जीवित करने का प्रयास करती है।

50. सक्रिय फार्मास्टीकल अवयवों (ए पी आई) पर दिनांक 24 सितंबर, 2015 की कटोच समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य नियामक प्राधिकारों को शामिल कर ए पी आई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये एक दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता है जिसमें पाटनरोधी जैसे उपायों के विवेकपूर्ण और उदार उपयोग शामिल हों।
51. “भारतीय फार्मा के लिए प्रवृत्तियां और अवसर” पर फरवरी 2018 की फिक्की की रिपोर्ट का संस्करण इस बात पर बल देता है कि ए पी आई आपूर्ति के लिये चीन पर निर्भरता फार्मा उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति में बाधाओं और कीमत में उतार चढ़ाव के प्रति अरक्षित करता है।
52. भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्टीकल आयुष विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय जापन के माध्यम से देश में ए पी आई के बढ़े हुये उत्पादन के लिये एक रोडमैप तैयार करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया क्योंकि फार्मास्टीकल क्षेत्र में इन अवसरों का उपयोग करने के लिये संकेंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।
53. पूर्व निर्णायक समीक्षा जांचों में शुल्क को प्रभावी रूप से लगाये जाने के बाद, विभिन्न उत्पादकों ने इस देश में नये निवेश किये हैं। लगभग 40.86 करोड़ रुपए और 20000 मी. ट. तक की कुल क्षमताओं के लिए अंतिम संरक्षण के बाद इस उद्योग में निवेश किया गया है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी और ये निवेश खतरे में पड़ जायेंगे।
54. पैरासिटामोल उद्योग लघु कंपनियां हैं जो बहुत अधिक प्रभावित होने के लायक और कीमत संवेदनशील हैं। विगत में विभिन्न पैरासिटामोल उत्पादकों को उत्पादन स्थगित करने की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि वे कम कीमत पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को जोखिम उठाना पड़ सकता है।
55. सामान्य तौर पर आम जनता को पहले से ही एक नियामक तंत्र के माध्यम से बहुत अधिक संरक्षण दिया गया है क्योंकि पैरासिटामोल फार्मास्टीकल नीति 2015 में आवश्यक दवा की राष्ट्रीय सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है।
56. पैरासिटामोल इस देश में उपलब्ध सबसे सस्ती ए पी आई में से एक है।
57. उस अवधि जिसके लिए शुल्क लागू रहा है कि कोई संगतता इस कानून के अंतर्गत इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को आगे की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता है या नहीं। शुल्क के विस्तार की वास्तविक जांच यह है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में फिर से होने की संभावना है और न की उस अवधि के लिए जिसके लिए शुल्क लगाया गया है।
58. घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे इस कीमत जिस पर उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्रत्यक्ष रूप से इस उत्पाद का निर्यात किया है और वह कीमत जिस पर इस प्रकार के उत्पादकों ने भारत में अंतिम निर्यात के लिये व्यापारियों को यह सामग्री दी है, से तुलना करें। याचिकाकर्ता की समझ यह है कि उत्पादकों ने इस सामग्री को उस कीमत पर बेचा है जो उस कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कम है जिस पर व्यापारियों ने भारतीय बाजार में इस उत्पाद की बिक्री की है। इसके अलावा, उत्पादकों ने इस उत्पाद को भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से बीजक भी भेजा है। केवल व्याख्या के उद्देश्य से, यदि इन उत्पादकों ने इस उत्पाद का बीजक भारत में 100 यू एस डॉलर प्रति एकक की दर से भेजा है तब उन्होंने इन व्यापारियों को 75 यू एस डॉलर की दर से बीजक भेजा है और इन व्यापारियों ने इन वस्तुओं का बीजक भारत में 105 यू एस डॉलर की दर से भेजा है। इस प्रकार से जब उत्पादकों को भारतीय ग्राहकों/ उपभोक्ताओं की जानकारी भी है और उन्होंने भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर कथित रूप से इस उत्पाद को बेचा है, उन्होंने इस उत्पाद को व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेचा है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि वह कीमत जिस पर इन उत्पादकों ने व्यापारियों को इस उत्पाद की बिक्री की है वास्तविक कीमतें हैं जिस पर इस अवधि में व्यापार हुआ है।
59. घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के अपने पूर्व की अंतिम जांच परिणामों में पहले ही यह मान लिया है कि चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमताएं हैं और चीन के उत्पादक निर्यातक उन्मुख हैं और उस पर इसमें विश्वास किया गया है।

60. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि भारत औसत के आधार पर कोई विश्लेषण कम से कम बहुत अधिक भ्रामक है। प्रत्येक बिक्री लेन देन प्रत्येक निमाता द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई है और इसके आधार का संबंध किसी अन्य से नहीं है। यदि तीसरे देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किये जाते हैं तब इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई अनुरोध/ औचित्य नहीं है कि क्यों उन बिक्रियों को भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित नहीं किया जायेगा। उत्तर देने वाले निर्यातकों ने तीसरे देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बिक्री करने के लिये कोई बाध्यता अथवा कोई अन्य कारण तथा कोई ऐसा कारक नहीं दर्शाया है जो उन्हें उन कम कीमत वाली बिक्रियों को भारत में परिवर्तित किये जाने की रोक पायेगा। ऐसा लगता है कि चीन के उत्पादक चेरिटेबल संस्थान नहीं हैं और वे व्यापार संगठन हैं जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है।

ख) निर्यातको/ आयातको/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

61. निर्यातकों द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ऐसे अनुरोध कर रहे हैं जो विरोधाभासी हैं। एक ओर घरेलू उद्योग चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आधार पर पाटन और पाटन की संभावना का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर वे यह उल्लेख करते हैं कि चीन से आयात अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर किये जाते हैं और इस कारण से आयातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों के समर्थन में रिकार्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण से घरेलू उद्योग के अनुरोधों में कोई दम नहीं है। शुल्क मुक्त योजनाओं के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में यह देखा जा सकता है कि निर्यात किये किये पैरासिटामोल फामुलेशन के लिये संबद्ध वस्तुओं की मांग को आयातों की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण चीन से आयातों से पूरा किये जाने की पूरी संभावना है और इस प्रकार के आयात किये जाते रहेंगे क्योंकि ये आयात पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन नहीं होंगे। इस प्रकार से, उत्पाद की प्रकृति और विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात उस सीमा तक आसन्न रहेंगे।
62. घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2018 – मार्च 2019 की अवधि के लिये उपलब्ध कराये गये आयातों की सूचना का स्रोत नहीं दिया है। इस प्रकार से आपूर्ति की गई सूचना के आधार पर भी यह देखा जा सकता है कि उनके अनुरोधों में कोई दम नहीं है क्योंकि इस जांच में पूर्व के अंतिम जांच परिणामों को 29 जनवरी, 2019 को जारी किया गया था और शुल्कों को वापस लेने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना 16 अप्रैल, 2019 को जारी की गई थी और ये शुल्क माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए आज भी जारी हैं और उन्हें बंद नहीं किया गया है। यह देखा जा सकता है कि वह स्थिति जो उपर्युक्त अंतिम जांच परिणामों के जारी किये जाने के पूर्व विद्यमान थी, उपर्युक्त जांच परिणामों के जारी किये जाने के बाद भी वही है। इस कारण से घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों में कोई दम नहीं है कि अंतिम जांच परिणामों को जारी किये जाने के बाद आयातों में वृद्धि हुई है।
63. हेबेइझियांग की क्षमता उपयोग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और यह क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान कमोवेश उसी क्षेत्र में रही है। बिक्री के संबंध में भी, यह देखा जा सकता है कि वह क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान कमोवेश एक जैसी रही है। बिक्री कीमतों के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान घरेलू कीमतें और भारत को किये गये निर्यातों की तुलना की जा सकती है। यह भी देखा जा सकता है कि हेबेइझियांग द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं का किया गया निर्यात उनके आयातों के आधार पर किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि इन निर्यातकों द्वारा जिनका प्रतिनिधित्व हमारे द्वारा किया जाता है अन्य देशों को निर्यात का लेन देन वार ब्यौरा पहले ही प्रस्तुत किया गया है और यह रिकार्ड का मामला है।
64. भारतीय बाजार निर्यातकों के लिए कीमत आकर्षक नहीं है क्योंकि अन्य देशों के लिए उनके द्वारा औसत आधार पर वसूली जाने वाली कीमत भारतीय कीमतों की तुलना में अधिक है।
65. चीन में और अन्य देशों में विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हुआ है और वह क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान कमोवेश एक जैसी रहती है।
66. पाटनरोधी जांच में, शुल्कों को लगाये जाने का निर्णय पाटन अथवा पाटन और क्षति की संभावना पर निर्भर है और इसका घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता के विस्तार में किये गये निवेश से कोई संबंध नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय यूनियन, इण्डोनेशिया, इरान और जापान से मेलामाइन एस एस आर जांच में उसे माना।

67. जनहित का विचार करना एक कानूनी स्थिति नहीं है जिसकी जांच शुल्क को जारी रखने, उसे लगाने अथवा उसे वापस लेने अथवा उसे समाप्त करने अथवा जांच के लिए पाटनरोधी पर भारतीय कानून के अनुसार किये जाना है।
68. निर्यातकों द्वारा यह दोहराया गया है कि चीन जन. गण. से ड्राई सैल बैटरियों के मामलों में (मामला सं. 15/12/2011 – डी जी ए डी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 मई, 2013), प्राधिकारी द्वारा यह माना गया था कि 10 वर्षों से आगे पाटनरोधी शुल्क केवल विशेष मामलों में लगाया जाये। वर्तमान मामला एक विशेष मामला नहीं है जहां शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित है। विचाराधीन उत्पाद के लिए शुल्क पिछले 17-18 वर्षों से लागू रहा है।

च. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

69. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों का उद्देश्य घरेलू खपत नहीं है और इस कारण से इसका घरेलू उद्योग की कीमतों और क्षति की परिणामी संभावना पर कोई प्रभाव नहीं है।
70. 17 वर्षों की अवधि से आगे शुल्क जारी रखे जाने के संबंध में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन शुल्कों को विगत में तभी बढ़ाया गया था जब जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था कि शुल्क के समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
71. इस अनुरोध के संबंध में की वैश्विक उत्पादन का 86 प्रतिशत भारत और चीन में है जिसमें से उत्पादन का 62 प्रतिशत चीन में और भारत में 24 प्रतिशत है। इस कारण से इस उद्योग में किसी प्रकार की रुग्णता के कारण वैश्विक मांग चीन के उत्पादकों की दया और एकाधिकार पर निर्भर रह जायेगा, यह उल्लेख किया जाता है कि भारत की मांग का केवल 6 प्रतिशत को आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है और घरेलू उद्योग सक्षम रूप से कार्य कर रहा है।
72. डी जी सी आई एंड एस आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा जाता है कि आयातों में जांच की अवधि में 2969 मी. ट. से जांच की अवधि के बाद की अवधि में 988 मी. ट. तक गिरावट आई है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में 250 रु. प्रति किलोग्राम से बढ़कर 362 रु. प्रति किलोग्राम हो गया है।
73. जहां तक सहयोगी निर्यातकों की क्षमता के उपयोग का प्रश्न है यह नोट किया जाता है कि प्रमुख निर्यातक जिन्होंने चीन के सहयोगी उत्पादकों से कुल निर्यातों का 80 प्रतिशत निर्यात किया है। वर्ष 2016-17 में 68.7 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 71 प्रतिशत हो गया है।
74. जहां तक भारत की कीमत आकर्षकता का प्रश्न है, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से विश्व के शेष देशों में निर्यात के संबंध में चीन जन. गण. के सीमा शुल्क आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो यह दर्शाता है कि तीसरे देशों को निर्यातों की कुल मात्रा का 28.6 प्रतिशत उस कीमत पर हुआ है जो उस कीमत जिस पर भारत को चीन द्वारा निर्यात किया गया है, की तुलना में कम है। जबकि कुल निर्यातों की 64.1 प्रतिशत की कीमत उन दरों पर लगाई गई है जो भारत को संबद्ध वस्तुओं का चीन द्वारा निर्यात की जा रही कीमतों की तुलना में अधिक है।
75. इस अनुरोध के संबंध में की वह कीमत जिस पर उत्पादकों ने व्यापारियों को इस उत्पाद की बिक्री की है वास्तविक कीमतें हैं जिस पर इस अवधि में व्यापार हुआ है, यह उल्लेख किया जाता है कि वास्तविक कीमतें वे कीमतें हैं जिन पर समग्र रूप में चीन देश भारत को निर्यात किया है जिसके लिए पहुंच मूल्य की गणना 3828/ मी. ट. यू एस डॉलर पर की गई है जो घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत की तुलना में अधिक है और न की उन कीमतों की तुलना में अधिक है जिन पर उत्पादकों ने चीन जन. गण. में व्यापारियों को उत्पाद की बिक्री की है।
76. प्राधिकारी इन आवेदकों द्वारा ए पी आई और बाजार संबंधी अन्य सूचना जैसे फिक्की की रिपोर्ट के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में अनुरोधों को नोट करते हैं।
77. पाटन विश्लेषण का ब्यौरा संगत शीर्षों के अंतर्गत दिया गया है।
78. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अन्य अनुरोधों की जांच संगत शीर्षों के अंतर्गत की गई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

79. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात निर्यातकों को उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए :-

- i. मै. एंक्विलू लून फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- ii. मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लिमि.,
- iii. चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन,
- iv. झेजियांग कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन,
- v. लियानुगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vi. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vii. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,

80. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1) (ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

“ व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यांनांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ज. घरेलू उद्योग के विचार

81. वर्तमान जांच और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. चीन को इस कारण से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने की जरूरत है कि चीन में लागत और कीमतें बाजार दबावों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते। अनुबंध-1 का पैरा 8 उन मापदंडों को निर्दिष्ट करते हैं जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करते समय विचार किया जाना चाहिए। यह भी समाविष्ट करते हैं कि जब तक इन शर्तों को पूरा/संतुष्ट नहीं किया जाता, चीनी लागतों और कीमतों को नहीं अपनाया जा सकता।
- ii. चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के अंतर्गत प्रचालन करने वाली कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा-7 क आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं।
- iii. आयात भारतीय बाजारों में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं।

- iv. विभिन्न आयात सौदों की कीमतों में अंतर है जिसका तात्पर्य है कि चीनी उत्पादक समान उत्पाद की ऐसी कीमत पर बिक्री कर रहे हैं जो समान समय अवधि पर भी उल्लेखनीय रूप से भिन्न है और यह पीओआई की एक विशिष्ट परिघटना नहीं है बल्कि संपूर्ण क्षति अवधि में विस्तारित है।
- v. यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारांशित औसत सामान्य मूल्य की भारांशित औसत निर्यात कीमत के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी से भारांशित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन करने और इसकी पृथक निर्यात कीमत के साथ तुलना करने का अनुरोध किया जाता है और उन सभी आयात सौदों में, जहां पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, इसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल किए जाने की जरूरत है।
- vi. समान समय पर रिपोर्ट किए जा रहे आयातों के संबंध में कीमतों में ऐसे उल्लेखनीय अंतर की कोई युक्तियुक्त कारण/ औचित्य नहीं है।

ज. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

82. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. वर्तमान जांच में संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित किया गया है, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, वर्तमान जांच में याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है।
- ii. वर्तमान जांच में चीन, जन. गण. में कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य कृपया घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- iii. यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों पर आधारित न होने के कारण चीनी उत्पादकों की घरेलू कीमतों या लागतों की उपेक्षा करने के लिए 15 वर्षों की अवधि, जैसाकि डब्ल्यू टी ओ के लिए चीन जनवादी गणराज्य के परिग्रहण प्रोटोकॉल के पैरा 15(क)(ii) में व्यवस्था की गई है, पैरा 15 (घ) की शर्तों में 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई हैं और यह प्रचालनहीन हो गया है।
- iv. इस समय, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो माननीय प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों को उनकी घरेलू कीमतों और लागतों की उपेक्षा करने के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का प्रचालन करने के रूप में विचार करने में सक्षम बनाता है और चीन के लिए सामान्य मूल्य को उनकी घरेलू कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- v. चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त कोई अन्य पद्धति डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत भारत की बाध्यताओं के उल्लंघन में होगी।
- vi. उपर्युक्त अनुरोध के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि किसी अतिरिक्त कार्यविधि का अनुसरण किए बिना चीनी निर्यातकों के लिए उनके रिकॉर्डों के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान किया गया है, घरेलू उद्योग ने यथोचित कार्य विधि, जैसी कि भारतीय पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई है, का अनुसरण किए बिना चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का मनमाने ढंग से निर्धारित किया है।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित निर्मित सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत और 5 प्रतिशत पर लाभ की दर विचारित करने पर आधारित है। तथापि, निर्मित सामान्य मूल्य को मदवार विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- viii. भारतीय लागतों और कीमतों पर आश्रित पद्धति का केवल तभी अनुसरण किया जाना चाहिए जब पैरा 7 के प्रारंभिक वाक्य में निर्धारित अन्य विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्मित करना संभव नहीं हो।
- ix. पैरा 7 के प्रावधानों की शर्तों में, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान किया जाना जरूरी है और केवल वहां, जहां ऐसे तीसरे देश से जरूरी आंकड़े प्राप्त करना संभव

नहीं हो, एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि अनिवार्य हो, सामान्य मूल्य को किसी अन्य उचित समायोजित आधार, जिसमें सामान्य उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत शामिल है, पर निर्धारित किया जा सकता है।

- x. घरेलू उद्योग संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में किसी उचित विलंब के बिना सूचित करने के लिए बाध्य है, ताकि इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
- XI. कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य कार्य विधि का अनुसरण नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को तीसरे देश के चयन के बारे में नोटिस नहीं दिया गया है। न ही हितबद्ध पक्षकारों से तीसरे देश के बारे में सुझाव देने और अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराने के बारे में अनुरोध किया गया है।
- XII. अनिवार्य कार्य विधि का अनुसरण किए जाने के अभाव में, शेनयांग मात्सुशिता 2005 (181) ई एल टी 320 (एस सी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्यवाही को जारी नहीं नहीं रखा जा सकता।
- XIII. पैरा 7 की अनिवार्य कार्यविधि का अनुसरण करने में असफलता को सामान्य मूल्य के निर्धारण पर और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन पर पर्याप्त निहितार्थ हैं।
- XIV. इसलिए, वर्तमान जांच में अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने के लिए माननीय प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

क. चीन में सामान्य मूल्य

83. जांच शुरूआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत नोटिस का उत्तर देने और सामान्य मूल्य के निर्धारण की संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंड के अनुसरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा के खंडन के लिए सभी जात उत्पादकों/ निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन सरकार से उनके देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देने का अनुरोध किया। हालांकि, चीनी उत्पादकों में से किसी ने भी प्राधिकारी द्वारा जारी अनुपूरक प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया।
84. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

ख. चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

85. चूंकि, चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है। अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना की अनुपस्थिति में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में प्रतिष्ठापित किया गया है, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पद्धति को अपना कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
86. अतः प्राधिकारी ने भारत में समुचित रूप से समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। तदनुसार, चीनी निर्यातकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य *** रूपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

ग. चीन जन. गण. में निर्यात कीमत का निर्धारण

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से नीचे उल्लिखित निर्यातकों ने प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई है जिसे निर्यात कीमत और पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयोग किया गया था।

- i. मै. एनक्यू अन फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- ii. मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लिमि.,
- iii. चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन,
- iv. झेजियांग केमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन,
- v. लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vi. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vii. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,

88. दायर किए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तरों का निम्नानुसार विश्लेषण किया है :-

क) मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक) और मै. ए एच ए इंटरनेशनल कं. लि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड झेजियांग केमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लि. ने भारत को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन निर्यात किया है और *** मी.टन अपने ट्रेडर्स मै. ए एच ए इंटरनेशनल कंपनी लिमि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और झेजियांग केमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कंपनी ने *** अम. डॉ./ मी.ट. की निर्यात कीमत रिपोर्ट की है और वहीं ए एच ए इंटरनेशनल कं. लिमि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और झेजियांग केमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने क्रमशः *** अम. डॉ., *** अम. डॉ./ मी.ट. और *** अम. डॉ./ मी.ट. की निवल निर्यात कीमत रिपोर्ट की है।

90. उत्पादकों/ निर्यातकों ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, समुद्री माल भाड़ा और समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैंट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उक्त उत्पादक और इसके संबंधित ट्रेडर्स की भारित औसत निर्यात कीमत को तत्पश्चात उक्त निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों की कुल मात्रा पर विचार करते हुए इसे *** अम. डॉ./ मी.ट. पर निर्धारित किया गया है।

ख. मै. लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक) और मै. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. ने अपने ट्रेडर्स मै. अर्थात् झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि. के माध्यम से *** मी.ट. निर्यात किया है। उन्होंने अंतर्देशीय मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैंट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। उत्पादक/ट्रेडर द्वारा दावा किए गए समायोजन के पश्चात, प्राधिकारी ने *** अम. डॉ./मी.ट. के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत को निर्धारित किया है।

ग. मै. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक)

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि. ने भारत को सीधे ही *** मी.ट. निर्यात किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैंट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, उत्पादक/ व्यापारी द्वारा दावा किए गए व्ययों के समायोजन के पश्चात, प्राधिकारी ने *** अम. डॉ./ मी.ट. के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की है।

93. संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे तालिका में दिये गये अनुसार किया गया है :-

छ. 4 पाटन मार्जिन का निर्धारण

कंपनी का नाम (उत्पादक) (पीओआई)	कंपनी का नाम (निर्यातक)	सीएनवी अम. डॉ./मी.ट.	एनईपी अम. डॉ./ मी.ट.	पाटन मार्जिन अम. डॉ./ मी.ट.	डीएम %	रेंज
मै. एन्क्यू लू एन फार्मास्युटीकल कं. लि.	मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
	चाइना सिनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन					
	झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन					
लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.	झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.	***	***	***	***	0-(10)
हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि.		***	***	***	***	10-20

52. संबद्ध देश

(क) समग्र रूप में देश के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए, संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

विवरण अम.डॉ./ किग्रा.— रू./किग्रा. (पीओआई)	अम.डॉ./किग्रा.	रू./किग्रा.
सामान्य मूल्य	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***
रेंज %	10-20	10-20

ज. क्षति निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच**ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

94. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- निर्णायक पुनरीक्षा का स्वरूप मूल जांच से भिन्न है क्योंकि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना पर अधिक ध्यान केन्द्रित होता है। पुनरीक्षा मामलों के लिए वर्तमान क्षति अथवा वर्तमान पाटन की उपस्थिति की जांच करना जरूरी नहीं समझा गया है जहां क्षति की संभावना अधिक महत्वपूर्ण है।
- क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव हुआ होता तो पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त होने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी।

- iii. यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, भावी घटनाओं की एक प्रति तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो पाटित आयातों, कीमतों और घरेलू उद्योग पर के प्रक्षेपित स्तर पर आधारित होगा।
- iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से हानि होने की संभावना है, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है।
- v. इस समय ऋणात्मक कीमत कटौती विद्यमान है। यह प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने पर स्थिति के विपरीत होने की संभावना है।
- vi. पाटनरोधी शुल्कों के प्रवृत्त होने के कारण विक्रय कीमत और आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त करने की स्थिति में, आयातों से कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव होने की पूरी संभावना है।
- vii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रयों में वृद्धि हुई है। हालांकि, इस स्तर पर वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने से क्षमता उपयोग में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आएगी।
- viii. आधार वर्ष के बाद से घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ तथा आय में वृद्धि हुई है।
- ix. पूरी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से पाटित आयात का उल्लेखनीय मात्रा में प्रवेश दुबारा आरंभ हो जाएगा जो घरेलू बाजार का बाजार हिस्सा अभिग्रहित कर लेंगे।
- x. अधिकतर मापदंडों की शर्तों में घरेलू उद्योग की वृद्धि ने सुधार दर्शाया है। यह प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में स्थिति के विपरीत होने की संभावना है।
- XI. वर्तमान मामले में, संबद्ध देश से निर्यात कीमत समय अवधि की शर्तों में उल्लेखनीय रूप से भिन्न है और इसलिए यह एक उचित मामला है जहां भारित औसत सामान्य मूल्य की भारित औसत निर्यात कीमत के साथ तुलना नहीं की जा सकती।
- XII. निर्दिष्ट प्राधिकारी से भारित औसत सामान्य मूल्य पर विचार करने और इसकी पृथक निर्यात कीमत के साथ तुलना करने का अनुरोध किया जाता है और उन सभी आयात सौदों में जहां पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, वहां इसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल न किए जाने की आवश्यकता है।
- XIII. अवधि, जिसके लिए शुल्क प्रवृत्त है, यह निर्धारण करने के लिए असंगत है कि क्या शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता है। कानून में शुल्कों के विस्तार की व्यवस्था की गई है यदि ऐसे शुल्कों को निरस्त करने के कारण पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है। अन्य देशों जैसे कनाडा, यूएसए, ब्राजील और यूरोपीय संघ के अभ्यास के अनुसार, शुल्कों के 15 से अधिक वर्षों के लिए लागू किया जा सकता है, चाहे संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात न हो रहा हो।

ज. 2 निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

95. निर्यातकों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :-

- i. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और क्षति जांच अवधि में घरेलू उद्योग के सभी क्षति मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- ii. संबद्ध वस्तुओं के आयात के प्रति पाटनरोधी शुल्क 17 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और वर्तमान मामला कोई विशेष मामला नहीं है जहां शुल्कों को और 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है।

- iii. संबद्ध देश से भारत को आयातों की बहुलता शुल्कमुक्त योजना के अंतर्गत है जैसे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्रिम लाइसेंस, डी ई पी बी आदि, जो शुल्क के अधीन नहीं हैं।
- iv. चाहे ऐसे आयातों को क्षति के विश्लेषण और क्षति की संभावना के लिए शामिल किया गया है और पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा की गई है, तथापि उक्त शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए आयात किसी पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन नहीं होंगे और भारत में प्रवेश करते रहेंगे।
- v. माननीय प्राधिकारी के समक्ष सभी चार जांचों में घरेलू उद्योग के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसलिए, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस समय घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।
- vi. भारत में जांच अवधि में 579 करोड़ रुपये की बिक्री करने वाले संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादक अर्थात् ग्रेन्यूल्स इंडिया को सभी 3 निर्णायक समीक्षा से अलग रखा गया है और कोई क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सभी 3 निर्णायक समीक्षा जांचों में सीमित सूचना के आधार पर क्षति और क्षति की संभावनाओं का विश्लेषण घरेलू उद्योग की स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता और इसलिए वर्तमान मामले में, शुल्क को और 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।
- vii. चीन जन. गण. (मामला सं. 15/2/2011-डी जी ए डी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 मई, 2013) से ड्राई सैल बैटरीज से संबंधित अंतिम जांच परिणाम को जारी करते समय प्राधिकारी ने धारित किया है कि 10 वर्षों के बाद भी पाटनरोधी शुल्कों को केवल विशेष मामलों में लागू किया जाना चाहिए।
- viii. यदि, पाटनरोधी शुल्क का विस्तार न किए जाने के पश्चात संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि होती है तो घरेलू उद्योग कभी भी नए पाटनरोधी जांच को आरंभ करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

96. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि वह पहले रद्द न किया गया हो, ऐसे प्रत्यारोपण की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव करना बंद कर देगा बशर्ते कि यदि किसी पुनरीक्षा में, केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है, तो वह समय-समय पर, ऐसे प्रत्यारोपण की अवधि को और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ सकती है और ऐसी विस्तारित अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
97. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसरण में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर विचार किया है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्रय मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।
98. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
99. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच

करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

100. इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति□ के संभावित पहलुओं की जांच को आगे बढ़ाने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति□ यदि कोई हो, की जांच को आगे बढ़ाया है।

(i) मांग/ प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण

101. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या प्रत्यक्ष खपत को परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग नीचे दी गई है :-

*अप्रैल 17 से मार्च 18

मांग	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	108	108
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	108	110
से आयात					
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2969
अन्य देश	मी.ट.	79	115	30	65
कुल मांग	मी.ट.	48,251	50,295	49,603	50,835

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में मांग ने वृद्धि दर्शायी है, हालांकि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2016-17 में मामूली गिरावट आई है। मांग में पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष दोनों की तुलना में जांच की अवधि में एक बार फिर वृद्धि हुई।

(ii) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव : आयात और बाजार हिस्सा

103. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना अनिवार्य है कि क्या या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीचे दी गई सारणी आयात मात्रा और बाजार हिस्से के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति□ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है:-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई	जांच की अवधि के बाद की अवधि 2018-19
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2,969	981
अन्य देश	मी.ट.	79	115	30	65	43
कुल आयात	मी.ट.	4,434	2,045	2235	3034	1024
मांग में बाजार हिस्सा						--

घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***	--
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	--
संबद्ध देशों से आयात	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%	--
अन्य देशों से आयात	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%	--
कुल मांग	%	100	100	100	100	--

104. यह देखा गया है कि आयात मात्रा में 2015-16 तक गिरावट आई और तत्पश्चात उसमें वृद्धि हुई। इसके अलावा, आयातों में जांच की अवधि में 2969 मी. ट. से जांच की अवधि की बाद की अवधि में 981 मी. ट. तक कमी आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सा कमोवेश स्थिर बना रहा है।

(iii) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

105. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा उल्लेखनीय रूप से घटित हुआ होता। इस संबंध में, उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटाकर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना की है।

कीमत कटौती

विवरण	इकाई	पीओआई
चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत	Rs./Kg	250.06
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	(***)
कीमत कटौती	%	(***)
रेंज		(0-10)

उपर्युक्त से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।

106. घरेलू उद्योग के अनुरोधों और विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों में इस बात में कोई विवाद नहीं है कि संपूर्ण आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए थे और इसलिए इन आयातों पर न तो सीमा शुल्क न ही एडीडी अदा किए गए थे।

ख. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

107. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास करता है अथवा कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करता है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति□ अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति□ नीचे दी गई सारणी के अनुसार दर्शायी गई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
बिक्री की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	89	87	99
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	93	89	103
आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	265	266	238	250
प्रवृत्ति		100	102	87	94

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि पी ओ आई में आधार वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, पी ओ आई में बिक्रियों की लागत में मामूली गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में, पी ओ आई में संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पूर्ण क्षति की अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में वृद्धि के समानुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है। इसलिए, कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

(iv) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

110. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है:-

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

111. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	103	111	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	103	111	126
पीयूसी के लिए घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	113	116	117

112. उपर्युक्त जानकारी से, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- क) अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।
 ख) घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग क्षति अवधि में स्थिर बने रहे हैं।

ख) मांग

मांग	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	108	108
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	108	110
से आयात					
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2969
अन्य	मी.ट.	79	115	30	65
कुल मांग	मी.ट.	48,251	50,295	49,603	50,835

113. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बिक्री में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है।

ड) मांग में बाजार हिस्सा

114. मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
अन्य देश से आयात	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
कुल मांग	%	100	100	100	100

115. ये देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।

क. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

116. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
लाभ/(हानि)	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	375	225	325
नकद लाभ	लाख रूपाए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	165	255
पूंजीगत निवेश पर आय – एनएफए	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	90	136

117. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर आय में वृद्धि हुई है।

क. मालसूची

118. घरेलू उद्योग के पास माल सूचियां निम्नानुसार हैं :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
औसत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	125	130

119. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का औसत मालसूची स्तर एक वृद्धिकारक प्रवृत्ति□ दर्शाता है।

ख. रोजगार, लाभप्रदता और वेतन

120. रोजगार उत्पादकता और वेतन के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	119
मजदूरी	लाख रूपाए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	138	168
उत्पादकता/व्यक्ति/दिवस	किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	94	106

121. उपर्युक्त से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

झ. क्षति का परिमाण और क्षति मार्जिन

122. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति-रहित कीमत, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है, पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार तैयार किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	चीन (पी ओ आई)
1	आयात मात्रा	मी.ट.	2969
2	क्षति रहित कीमत	रू./किग्रा.	***
3	पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	250
4	क्षति मार्जिन	रू./किग्रा.	(***)
5	क्षति मार्जिन	%	(***)
6	क्षति मार्जिन रेंज		0-(10)

व. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

123. चूंकि, यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाए तो सतत पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की अब जांच करते हैं।

व. 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

124. पाटन जारी रहने और परिणामस्वरूप बार-बार क्षति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क (5) का अवलोकन स्पष्ट रूप से यह सुझाव देता है कि निर्णायक समीक्षा जांच के विधान के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना है :-
 - क्या पाटन जारी है और यदि हाँ तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है;
 - उस मामले में जहां पाटन जारी नहीं रहा था, क्या पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन फिर से होगा;
 - क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई और यदि हाँ तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है;
 - जिन मामलों में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में बार-बार होने की संभावना है;
- मूल जांच और परिणामस्वरूप निर्णायक समीक्षा जांचों में भी काफी पाटन की मौजूदगी सिद्ध हुई। पूर्व तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन काफी अधिक था।
- घरेलू बाजार तथा दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में चीन से संबद्ध सामानों के पाटन का एक लंबा इतिहास है।

- iv. सतत पाटन केवल अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के बाद ही कम हुआ था। उससे पूर्व घरेलू उद्योग को बहुत अधिक पाटित आयातों के कारण लगातार हानि उठानी पड़ रही थी जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समीक्षा मामलों में पूर्व में अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है।
- v. इन आयातों का महत्वपूर्ण स्तर 2015-16 से ही कम होना आरंभ हुआ। हालांकि यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि घरेलू उद्योग अभी भी पाटन के विगत क्षतिकारक प्रभावों से उबर रहा है और इस प्रकार से यह जोखिम पूर्ण स्थिति में है। पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने से संभवतः घरेलू उद्योग को तीव्र क्षति होगी।
- vi. ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को पिछले 15 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क संरक्षण मिला है, तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग को केवल पिछले 15 वर्षों से प्रभावी रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। चीन के उत्पादकों ने पाटन जारी रखा और उसके कारण पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद एक दशक तक घरेलू उद्योग को क्षति हुई।
- vii. निर्धारित मात्रा में निर्धारण से शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन से आयातों में कमी आई है। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से आयातों में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं। आयातों में गिरावट पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण है।
- viii. सतत पाटन के कारण विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले कई संयंत्र देश में बंद हो गए हैं जो निम्नलिखित हैं:
 - मैसर्स ट्रीटोन लैबोर्ट्रीज लि.
 - मैसर्स वामसी लैब्स लि.
 - मैसर्स श्रीनिवासा एग्रो इंडस्ट्रीज एंड ड्रग्स लि .
 - मैसर्स पैन ड्रग
 - मैसर्स एल्फा ड्रग
 - मैसर्स ग्लैक्सोमिथक्लाइन फार्मास्टीकल लि .
 - मैसर्स थेक्सा फार्मा प्रा.लि .
 - मैसर्स वानी फार्मा लैब्स लि.
 - रोहिणी केमिकल
 - फॉर्च्यून केमिकल
 - दिनेश फार्मास्टीकल
 - डॉजैन्स कंपनी .
 - साबू मेडिकेम
- ix. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन पूर्ण रूप से वैश्विक स्तर पर सीमित है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत भारत और चीन में है। केवल चीन में उत्पादन का 62 प्रतिशत है जबकि भारत में 24 प्रतिशत है। इस प्रकार से इस उद्योग में किसी प्रकार की रणता से वैश्विक मांग चीन के उत्पादकों की दया पर निर्भर करेगा।
- x. निर्यातकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों में संबद्ध सामानों का आयात है।
- xi. वर्तमान परिदृश्य में घरेलू उद्योग पाटन के प्रतिकूल प्रभावों से अब भी जूझ रहा है और उसने अपने आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में आंशिक वृद्धि दर्शाई है। यदि पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाते हैं तो वह वृद्धि विपरीत हो जाएगी।

- xii. घरेलू उद्योग उसके निष्पादन में और ह्रास नहीं है, इसका एक मात्र कारण यह है कि आयातों की मात्रा लागू शुल्कों के कारण थी। तथापि संबद्ध देश में उत्पादकों के पास काफी खाली क्षमताएं हैं जो भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में निर्यातों की इन अनुपयुक्त क्षमताओं का उपयोग करने और भारतीय बाजार में लाने की संभावना है।
- xiii. विदेशी उत्पादक निर्यात उन्मुख हैं क्योंकि उनकी क्षमताएं संबद्ध में घरेलू मांग से बहुत अधिक हैं। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2.21 लाख मी. ट. क्षमताओं की तुलना में 1 लाख मी. ट. की सीमा में है जबकि चीन में इस उत्पाद के लिए घरेलू मांग अपेक्षाकृत बहुत कम अर्थात् 20000 मी. ट. है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्यातकों ने संबद्ध देश में मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमताएं बना रखी हैं, 1 लाख मी. ट. के उत्पादन में से लगभग 80 प्रतिशत निर्यात के लिए है।
- xiv. निर्यातक न केवल भारत में केवल पाटन करते रहे हैं बल्कि अन्य देशों में भी पाटन करते हैं। इसके अलावा, उन कीमतों जिन पर इन वस्तुओं की आपूर्ति इन देशों को की गई है क्षतिरहित कीमत की तुलना में कम है। इस कारण से यह निष्कर्ष निकाला तर्कसंगत है कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब निर्यातक संभवतः भारत में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर बिक्री करेंगे।
- xv. वैश्विक रूप से विभिन्न देशों में संबद्ध देश से निर्यात कीमत संबद्ध देश से विभिन्न देशों को वैश्विक रूप से निर्यात के काफी अनुपात के संबंध में भारत में निर्यात कीमत से काफी कम है। इन तीसरे देशों के निर्यातों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन भारत में निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से अधिक हैं।
- xvi. चूंकि भारत तीसरे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कीमत आकर्षक बाजार है अतः निर्यातक अपने लाभ में वृद्धि करने और बाजार पर कब्जा करने के उद्देश्य से शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में अन्य देशों से भारत में अपने सामानों को परिवर्तित करने पसंद करेंगे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्यातकों की इन तीसरे देश के बाजारों में कोई प्रतिबद्धताएं नहीं हैं और उनके लिए अपने उत्पाद की कीमत का निर्धारण करने के लिए एकमात्र मापदंड उनके द्वारा प्राप्त कीमत है।
- xvii. शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट और इन आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन का अर्थ शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना है तथा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का स्वयं ही औचित्य बनाते हैं।

ब.2 निर्यातकों का अनुरोध

- 125. सीमा शुल्क तथा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, क्षति के बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
 - i. याचिकाकर्ताओं ने चीनी उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता उपलब्ध होने तथा उनके भारत को निर्यात किए जाने की संभावना के ब्यौरे नहीं दिए हैं, याचिकाकर्ता पाटन की संभावना का मामला बनाने में विफल रहे हैं।
 - ii. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है और वर्तमान जांच रद्द किए जाने योग्य है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 126. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए, क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की।
- 127. प्राधिकारी ने चीन सीमा शुल्क के अनुसार चीन से तीसरे देशों में किये गये निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे को नोट किया है जो यह दर्शाता है कि तीसरे देशों को 28.6 प्रतिशत निर्यात मात्रा उस कीमत से कम कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है और तीसरे देशों को 64 प्रतिशत निर्यात मात्रा उस कीमत से अधिक कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है।

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उनके अनुरोधों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना की जांच की है:

- क. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की बढ़े हुए आयात की काफी दर।
- ख. किसी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्न भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि।
- ग. क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव होगा तथा और आयातों के लिए मांग बढ़ने की संभावना होगी।
- घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।
उपर्युक्त मानदंडों में से प्रत्येक मानदंड का इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर रखी गई सूचना को देखते हुए तदनुसार विश्लेषण किया गया है।

(क) पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी दर

क्षति की अवधि और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि 2017-18	जांच की अवधि के बाद 2018-19
चीन	मी. ट.	4,356	1,930	2205	2969	981
अन्य	मी. ट.	79	115	30	65	43
अन्य आयात	मी. ट.	4,434	2,045	2,235	3,034	1024

* अप्रैल, 17 से मार्च, 18

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में 2969 मी. ट. से जांच की अवधि की बाद की अवधि में 981 मी. ट. तक गिरावट आई है।

130. यह भी देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में और जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से विक्री योग्य अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि

131. भारत को कुल निर्यात जांच की अवधि के दौरान 2969 मी. ट. था जिसमें से 2543 मी. ट. सहयोगी निर्यातकों से था।

132. प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों के पास मौजूदा अधिशेष क्षमताओं, क्षमता अभिवृद्धि, यदि कोई है, भारत को तीसरे देशों से व्यापार बदलने की संभावना, उत्तरदाता निर्यातकों के पास स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया है। विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है :

- क. भारत को तथा विश्व के शेष देशों को क्षमता, उत्पादन, अतिरिक्त क्षमताएं, निर्यात, भारत को निर्यात की मात्रा।

उत्पादक का नाम	यूनिट	एन्क्यु लु एन फार्मास्टीकल कं. लि.	लियानयुंगांग कंगले फार्मास्टीकल कं. लि.	हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्टीकल कं. लि.	कुल
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
उत्पादन (जांच की अवधि)	मी. टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
घरेलू खपत	मी. टन	***	***	***	***
भारत को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
आर ओ डब्ल्यू को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
कुल निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
निर्यातान्मुख %	रेंज %	35	54	39	39

ख. सहयोगी निर्यातकों की क्षमताओं के विश्लेषण के बाद प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों की क्षमताओं को नोट करते हैं जो नीचे दिए गए अनुसार है :

क्रम सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता (मी. टन प्रति वर्ष)
1.	अनहुई बीबीसीए लिक्वेंग फार्मास्टीकल	10,000
2.	चांगशू हुआगेंग फार्मास्टीकल	8000
3.	जियांग्सु वर्ल्ड काइंडली फार्मास्टीकल	10000
4.	वेनझोऊ फार्मास्टीकल फैक्ट्री	6,000
5.	जियांग्सू गुओहेंग फार्मा केमिकल्स कं. लि.	2,500
6.	रंकी ट्रेडिंग कं. लि.	12,000
7.	शंघाई बैलियन केमिकल्स कं. लि.	50,000
8.	लियानोयुआन सिटी बैकांग फार्मास्टीकल	500
9.	गैर-सहयोगी कंपनियों की कुल क्षमता	99,000
10.	असहयोगी उत्पादकों की कुल क्षमता	75,000
11.	चीन जन. गण. की कुल क्षमता	174,000
12.	भारतीय मांग	50,835

ग. सहयोगी उत्पादकों के विश्लेषण से यह देखा जाता है कि व्यापारी कंपनियों के पास उनकी अपनी उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं और वे अपने वेबसाइट पर उत्पादकों की क्षमता को उद्धृत करते हैं।

घ. उत्तर देने वाले उत्पादकों की क्षमता उपयोग और निर्यात उन्मुखीकरण तथा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि सहयोगी निर्यातक जो भारत को कुल निर्यात का

85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं कि चीन में बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं और सहयोगी उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण उत्पादन का 39 प्रतिशत है।

(ग) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची

133. चीनी उत्पादकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर यह दर्शाते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के पास मालसूची का स्तर भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक नहीं है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :

उत्पादक	यूनिट	2015	2016	2017	जांच की अवधि
मैसर्स एन्क्यु लु एन फार्मास्टिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
लियानयुंगांग कंगला फार्मास्टिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्टिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
कुल	मी. टन	48,251	50,292	46,603	50,835

(घ) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

134. अन्य देशों की तुलना में भारत को निर्यात कीमत और भारत को निर्यात की गई मात्रा का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है :

क्र. सं.	देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य अमेरिकी डॉलर	कीमत अमेरिकी डॉलर/ किग्रा.
1.	स्वीडन (एस ई)	200	2135	10.68
2.	स्वीजरलैंड (सी एच)	200	1960	9.80
3.	पुएर्तो रीको (पी आर)	76000	722540	9.51
4.	कोरिया डीपीआर (के पी)	7294	59996	8.23
5.	सेनगल (एस एन)	37200	275722	7.41
6.	न्यूजीलैंड (एन जैड)	36700	265774	7.24
7.	स्पेन (ई एस)	726182	4731798	6.52
8.	होन्डरस (एच एन)	2700	17247	6.39
9.	साइप्रस (सी वाई)	1510	9597	6.36
10.	पुर्तगाल (पी टी)	11000	69148	6.29
11.	ओमन (ओ एम)	75000	465278	6.20
12.	आस्ट्रेलिया (ए यू)	194061	1165226	6.00
13.	जमैका (जे एम)	550	3184	5.79
14.	तुनिसिया (टी एन)	97850	564678	5.77

15.	क्रोसिया गण. (एच आर)	18000	103048	5.72
16.	कज़ाकिस्तान (के जैड)	3000	16692	5.56
17.	अल्गेरिया (डी जैड)	371325	2043715	5.50
18.	अल्बानिया (ए एल)	255	1403	5.50
19.	उरुग्वे (यू वाई)	15075	81821	5.43
20.	रोमानिया (आर ओ)	113635	610836	5.38
21.	किरघिजिया	3150	16881	5.36
22.	कोरिया गण. (के आर)	917072	4800689	5.23
23.	अर्जेंटीना (ए आर)	131676	669468	5.08
24.	ग्रीस (जी आर)	26400	131646	4.99
25.	श्रीलंका (एल के)	22500	111160	4.94
26.	आलोस पी डी आर (एल ए)	1025	5060	4.94
27.	इटली (आई टी)	410574	2024742	4.93
28.	जापान (जे पी)	673277	3290755	4.89
29.	यूनाइटेड स्टेट्स (यू एस)	1329487	6478959	4.87
30.	मंगोलिया (एम एन)	13325	63689	4.78
31.	पनामा (पी ए)	65688	311056	4.74
32.	कोस्टा रिका (सी आर)	15500	73335	4.73
33.	मोलदाविया (एम डी)	200	940	4.70
34.	साउदी अरेबिया (एस ए)	57050	268095	4.70
35.	जर्मनी (डी ई)	783030	3673146	4.69
36.	गुएना (जी वाई)	500	2344	4.69
37.	मोरक्को (एम ए)	192450	900783	4.68
38.	फिनलैंड (एफ आई)	36000	168368	4.68
39.	पोलैंड (पी एल)	39895	185434	4.65
40.	परागुआ (पी वाई)	31550	146388	4.64
41.	हंगरी (एच यू)	317800	1469842	4.63

42.	फ्रांस (एफ आर)	2723382	12530613	4.60
43.	हैती (एच टी)	500	2300	4.60
44.	स्लोवेनिया रैप (एस आई)	70950	326288	4.60
45.	आयरलैंड (आई ई)	409446	1851772	4.52
46.	लैबनान (एल बी)	20300	91677	4.52
47.	कनाडा (सी ए)	322933	1456263	4.51
48.	इजरायल (आई एल)	12500	56197	4.50
49.	कम्पुचेया	192350	864025	4.49
50.	हॉंग कोंग (एच के)	93600	418493	4.47
51.	बुल्गोरिया (बी जी)	14000	62440	4.46
52.	चेक गण.	150000	664200	4.43
53.	मेकेडोनिया (एम के)	20000	88500	4.43
54.	यूनाइटेड किंगडम (जी बी)	321400	1418800	4.41
55.	डेनमार्क (डी के)	10750	47285	4.40
56.	नार्वे (एन ओ)	57000	249351	4.37
57.	कोटे डी लवोइरे	2200	9622	4.37
58.	जॉर्जिया (जी ई)	1500	6530	4.35
59.	सुडान (एस डी)	1050	4528	4.31
60.	इक्वेडोर (ई सी)	52050	222496	4.27
61.	जिम्बाब्वे	48500	205666	4.24
62.	वेनेजुला (वी ई)	31950	133412	4.18
63.	जॉर्डन (जे ओ)	163955	683314	4.17
64.	यूक्रेन (यू ए)	31010	129033	4.16
65.	मेक्सिको (एम एक्स)	228035	942760	4.13
66.	उज्बेकिस्तान (यू जैड)	97500	402696	4.13
67.	गण. यमन	7005	28702	4.10
68.	नीदरलैंड (एन एल)	642800	2612640	4.06

69.	बेलारूस	43768	176654	4.04
70.	फिलीपींस (पी एच)	420125	1680716	4.00
71.	इजिप्ट (ई जी)	1077390	4289120	3.98
72.	पाकिस्तान (पी के)	537515	2130457	3.96
73.	बेल्जियम (बी ई)	401000	1574454	3.93
74.	तुर्की (टी आर)	754759	2947147	3.90
75.	ग्वाटेमाला (जी टी)	128800	501363	3.89
76.	ब्राजील (बी आर)	1443432	5569782	3.86
77.	मलेशिया (एम वाई)	298155	1148139	3.85
78.	सिंगापुर (एस जी)	153250	590125	3.85
79.	इथोपिया (ई टी)	49625	189732	3.82
80.	कोलंबिया (सी ओ)	237661	907214	3.82
81.	पेरु (पी ई)	209575	798631	3.81
82.	लातविया (एल वी)	36000	136184	3.78
83.	चिले (सी एल)	89390	338000	3.78
84.	नाइगेरिया (एन जी)	2454182	9192619	3.75
85.	माली (एम एल)	17800	66067	3.71
86.	घाना (जी एच)	429510	1586019	3.69
87.	कैमरून (सी एम)	4025	14841	3.69
88.	म्यांमार (एम एम)	69735	256063	3.67
89.	निकारागुआ (एन आई)	8300	30433	3.67
90.	इएल साल्वडोर (एस वी)	55400	202809	3.66
91.	थाईलैंड (टी एच)	2475900	9061183	3.66
92.	बोलिविया (बी ओ)	11300	41351	3.66
93.	वियतनाम (वी एन)	2763850	10096528	3.65
94.	बंगलादेश (बी डी)	273000	995763	3.65
95.	डोमेनिकन गण. (डी ओ)	4850	17586	3.63

96.	जिबूती (डी जे)	13675	49564	3.62
97.	ताइवान (टी डब्ल्यू)	365950	1325995	3.62
98.	जॉर्जिया (जी ई)	1500	6530	4.35
99.	सुडान (एस डी)	1050	4528	4.31
100.	इक्वेडोर (ई सी)	52050	222496	4.27
101.	जिम्बाब्वे	48500	205666	4.24
102.	वेनेजुएला (वी ई)	31950	133412	4.18
103.	जॉर्डन (जे ओ)	163955	683314	4.17
104.	यूक्रेन (यू ए)	31010	129033	4.16
105.	मैक्सिको (एम एक्स)	228035	942760	4.13
106.	उज्बेकिस्तान (यू जैड)	97500	402696	4.13
107.	गण. यमन	7005	28702	4.10
108.	नीदरलैंड (एन एल)	642800	2612640	4.06
109.	बेलारूस	43768	176654	4.04
110.	फिलीपींस (पी एच)	420125	1680716	4.00
111.	इजिप्ट (ई जी)	1077390	4289120	3.98
112.	पाकिस्तान (पी के)	537515	2130457	3.96
113.	बेल्जियम (बी ई)	401000	1574454	3.93
114.	तुर्की (टी आर)	754759	2947147	3.90
115.	गुटेमाला (जी टी)	128800	501363	3.89
116.	ब्राजील (बी आर)	1443432	5569782	3.86
117.	मलेशिया (एम वाई)	298155	1148139	3.85
118.	सिंगापुर (एस जी)	153250	590125	3.85
119.	इथोपिया (ई टी)	49625	189732	3.82
120.	कोलंबिया (सी)	237661	907214	3.82
121.	पेरू (पी ई)	209575	798631	3.81
122.	लटविया (एल वी)	36000	136184	3.78

123.	चिली (सी एल)	89390	338000	3.78
124.	नाइजीरिया (एन जी)	2454182	9192619	3.75
125.	माली (एम एल)	17800	66067	3.71
126.	घाना (जी एच)	429510	1586019	3.69
127.	कैमरून (सी एम)	4025	14841	3.69
128.	म्यांमार (एम एम)	69735	256063	3.67
129.	निकारागुआ (एन आई)	8300	30433	3.67
130.	ईएल सालवाडोर (एस वी)	55400	202809	3.66
131.	थाइलैंड (टी एच)	2475900	9061183	3.66
132.	बोलिविया (बी ओ)	11300	41351	3.66
133.	विएतनाम (वी एन)	2763850	10096528	3.65
134.	बंगलादेश (बी डी)	273000	995763	3.65
135.	डोमिनिकन गण. (डी ओ)	4850	17586	3.65
136.	जिबूती (डी जे)	13675	49564	3.62
137.	ताइवान (टी डब्ल्यू)	365950	1325995	3.62
138.	इण्डिया (आई एन)	3080621	11128592	3.61
139.	कॉंगो डी ओर	89300	322233	3.61
140.	कूबा (सी यू)	16850	60660	3.60
141.	केन्या (के ई)	941170	3385483	3.60
142.	मॉरीसस (एम यू)	4000	14280	3.57
143.	इण्डोनेशिया (आई डी)	7667860	27314431	3.56
144.	साउथ अफ्रीका (जैड ए)	175600	624786	3.56
145.	इराक (आई क्यू)	191450	677055	3.54
146.	जाम्बिया (जैड एम)	119025	419477	3.52
147.	रूसिया (आर यू)	2015515	7039254	3.49
148.	इरान (आई आर)	81750	284072	3.47
149.	सीरिया (एस वाई)	289800	1005553	3.47

150.	बेनिन (बी जे)	39500	134850	3.41
151.	मोजाम्बिक (एम जैड)	68000	231030	3.40
152.	यूनाटेड अरब अमीरात (ए ई)	206600	686013	3.32
153.	तंजानिया (टी जैड)	268000	883641	3.30
154.	लिथुआनिया (एल टी)	42150	138818	3.29

स्रोत चीनी सीमा शुल्क

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों को 28.6 प्रतिशत कुल निर्यात मात्रा उस कीमत से कम कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है। जबकि 64.18 प्रतिशत कुल निर्यात उस कीमत से अधिक कीमत पर निर्यात किए जाते हैं जिस पर चीन भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करता है।

(ड) चीन जन. गण. में निर्यातोन्मुखता

136. चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा दायर प्रस्तुत किये गये अन्य साक्ष्य के अनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन में सहयोगी उत्पादक 39 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात उन्मुख हैं। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में इस बात की बहुत अधिक संभावना नहीं है कि निर्यातक/ उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन का सहारा लेंगे।

ट. कारणात्मक संपर्क और अन्य ज्ञात कारकों का योगदान न होने का विश्लेषण

137. सतत पाटन की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जांच करने के बाद भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए निम्नलिखित रूप में जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा एवं कीमत

138. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयातों का विवरण यह दर्शाता है कि अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयात न्यूनतम स्तर से कम पर आ रहे हैं। अतः अन्य देशों से आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले नहीं माना जा सकता।

ख. मांग में संकुचन और/ अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

139. संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग ने क्षति की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। यह भी नोट किया जाता है कि खपत के पैटर्न में कोई पर्याप्त परिवर्तन प्राधिकारी की जानकारी में नहीं आया है, न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

140. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो क्योंकि कच्ची सामग्री तथा संबद्ध सामान देश में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू उद्योग एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं और साथ ही संबद्ध सामानों के आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

141. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

142. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को वर्तमान क्षति मूल्यांकन के लिए प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग किया गया है। अतः निर्यात निष्पादन ने इस विवरण में प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया होता।

च. अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

143. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन का संबद्ध उत्पाद के सूचित किए गए निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन की जांच की है।

प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

ठ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

144. प्राधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन पश्चात् विवरण को प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि और समय 30 सितंबर, 2019 को 6.00 बजे अपराह्न तक था। हालांकि, इन टिप्पणियों की साफ्ट प्रति 30 सितंबर, 2019 को 6.55 बजे अपराह्न प्राप्त की गई थी। उसकी हार्ड प्रति 01.10.2019 को 5.00 बजे अपराह्न प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा विलंब से अनुरोध प्रस्तुत किये जाने के बावजूद प्राधिकारी ने नरम रुख अपनाया है और उनके उत्तरों पर विचार किया है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां अधिकांशतः पुनरावृत्ति हैं। हालांकि, उन टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया का समाधान किया गया है।
145. घरेलू उद्योग अपने आरंभिक अनुरोधों में प्राधिकारी द्वारा भेजे गये पत्र की प्रति और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों की प्रति के प्रकटन का अनुरोध करता है। घरेलू उद्योग ने विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को मेल अथवा पत्र के माध्यम से भेजे गये सभी पत्रों जिसमें प्रतिउत्तर और कार्यकारी द्वारा तैयार की गई सत्यापन रिपोर्ट शामिल है, की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
146. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि उस सूचना से लिये गये निष्कर्ष और व्याख्या पूर्व के प्रकटन विवरण/ अंतिम जांच परिणाम और मौजूदा प्रकटन विवरण में अलग अलग है।
147. सहयोगी उत्पादकों का उनके अलग अलग निर्यातकों के साथ लेन देन वार आंकड़ों का एक विश्लेषण किया गया जिससे कि पूर्व के प्रकटन विवरण और अंतिम जांच परिणाम में सहयोगी उत्पादकों के पाटित और क्षतिकारक आयातों को तय किया जा सके। वर्तमान प्रकटन में ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण को हटाने के कारण मौजूदा प्रकटन विवरण अपूर्ण हो गया है। इस प्रकार से अंतिम जांच परिणाम विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के अपूर्ण स्थापना पर आधारित होगा।
148. चीन में जहां चीन के उत्पादक अपने उत्पादन का 39 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं, में अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चीन में बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं।
149. क्षमता उपयोग का विश्लेषण उत्तर देने वाले निर्यातकों तक सीमित रखा गया है, यह निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा पर विचार नहीं करता है जिनका उल्लेख उन उत्पादकों द्वारा किया गया है जिन्होंने सहयोग को बरीयता नहीं दी है। यह तथ्य कि उत्तर देने वाले उत्पादकों का निर्यात भारत को किये गये कुल निर्यात का 85 प्रतिशत है। इस तथ्य के बारे में निर्णय लेने में पर्याप्त नहीं है कि क्या चीन के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं और वे निर्यात उन्मुख हैं। यह तथ्य कि क्षमता/ उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्से का उल्लेख असहयोगी उत्पादकों द्वारा किया गया है, को चीन के वैश्विक निर्यातों और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा तीसरे देश के निर्यातों से संबंधित होना चाहिए।
150. मौजूदा प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि चीन के उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि सहयोगी उत्पादकों के पास माल भंडार का स्तर भारतीय मांग की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि, पूर्व के प्रकटन विवरण ने विदेशी उत्पादकों के पास माल के बढ़ते हुए भण्डार को दर्शाया। ऐसे परिदृश्य में याचिकाकर्ता इस कथन के आधार को नहीं समझ पाये हैं कि क्या निर्यातकों के पास माल भंडार का स्तर बहुत अधिक नहीं है।
151. पूर्व के प्रकटन विवरण/ अंतिम जांच परिणामों में, चीन जन. गण. से निर्यात के संबंध में चीनी गणतंत्र के सीमा शुल्क आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के साथ, भारतीय कीमतें चीन के

उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए आकर्षक होगी। हालांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मौजूदा प्रकटन विवरण को जारी करते समय उसे हटा दिया।

152. पूर्व के अंतिम जांच परिणाम/ प्रकटन में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया कि चीन में उत्पादक वैश्विक रूप से निर्यातों के प्रति उन्मुख हैं जबकि मौजूदा प्रकटन में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन में उत्पादक 39 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात उन्मुख हैं। इस प्रकार से यह मौजूदा प्रकटन को अपूर्ण बना देता है।
153. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया कि प्रकटन विवरण के अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना किसी कारण के भाग लेने वाले निर्यातक/ उत्पादक के लिए किये गये पाटित और क्षतिकारक मात्रा के विश्लेषण को हटा दिया है। स्वीकार्य तौर पर वर्तमान जांच का संबंध घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना की जांच से संबंधित है। प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से सकारात्मक पाटन मार्जिन का दर्शाता है और इस कारण से पाटन की संभावना पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है। घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि भारत औसतों के आधार पर विश्लेषण बहुत अधिक भ्रामक हो सकता है। इन कारणों से, प्राधिकारी ने विगत में अनेक जांचों में अलग अलग निर्यात लेन देन पर विचार करते हुए विदेशी उत्पादकों के व्यवहार की जांच की है। इसके अलावा, भारत को तथा तीसरे देशों को किये गये निर्यातों पर विचार करते हुए यह विश्लेषण किया गया है। जबकि उत्तर देने वाले उत्पादकों ने भारत को किये गये निर्यात के संबंध में आंकड़े दिये हैं और प्राधिकारी उस स्थिति में है कि वे समान विश्लेषण कर सकें जहां तक तीसरे देशों को किये गये निर्यातों का प्रश्न है, निर्यातक असहयोगी हैं। इस प्रकार से जहां तक भारत को किये गये निर्यातों का प्रश्न है, चूंकि संबंधित सूचना रिकार्ड पर है अतः याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि वह भारत को किये गये बीजक निर्यातों के द्वारा बीजक पर विचार करते हुए जांच की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में जहां भारत को किये गये पर्याप्त हिस्से में निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं यह तथ्य कि भारत को किया गया कुछ निर्यात सामान्य मूल्य से अधिक है, यह सूचित नहीं करता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन की कोई संभावना नहीं है। इसके विपरीत भारत को किये गये अधिकांश निर्यात उस कीमत पर किया गया है जो सामान्य मूल्य से कम है, स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन की संभावना को सिद्ध करता है।
154. जहां तक तीसरे देशों को किये गये निर्यातों का प्रश्न है, चूंकि निर्यातों ने असहयोग को अपनाया है और तीसरे देशों को किये गये अलग अलग निर्यात लेन देन के संबंध में संगत सूचना रोक ली है, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे निर्यातकों पर (और घरेलू उद्योग के विरुद्ध नहीं) प्रतिकूल तथ्यों को लागू करें और यह मान लें कि वह स्पष्ट रूप से पाटन की संभावना को सिद्ध करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार करें जो सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बहुत अधिक मात्रा में निर्यात को दर्शाता है। घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार चीन से विभिन्न देशों में 15610 मी. ट. का निर्यात उस कीमत पर किया गया है जो सामान्य मूल्य से कम है। इसकी तुलना में सामान्य मूल्य से कम पर निर्यातों की इस मात्रा की तुलना में, भारतीय मांग केवल 50000 मी. ट. है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य से कम कीमत पर तीसरे देशों को 15610 मी. ट. निर्यात की तुलना में, 4000 मी. ट. का निर्यात उस कीमत पर किया गया था जो भारत में मौजूद बिक्री कीमत से कम है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में जहां निर्यातक तीसरे देशों को पाटित कीमत और वह कीमत जो भारत में बिक्री कीमत से कम है, पर 15610 मी. ट. की बिक्री कर रहा था, यह तथ्य सामने आता है कि ये निर्यातक पाटन कीमत पर इन निर्यातों को भारत में परिवर्तित करने की स्थिति में होंगे (और वास्तव में ऐसा करना चाहेंगे)। इस प्रकार से याचिकाकर्ता (घरेलू उद्योग) प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे कृपया पाटन और क्षति की संभावना को सिद्ध करने के उद्देश्य से 15610 मी. ट. की मात्रा पर विचार करें।
155. घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि मौजूदा प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों की क्षमताओं को नोट किया है परंतु उस क्षमता पर विचार नहीं किया है जो चीन के असहयोगी उत्पादकों के पास उपलब्ध है। घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे यह मानकर उनके असहयोग को पुरस्कृत नहीं करें कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं। विशेषकर, तब जब निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास (क) विभिन्न कंपनियों द्वारा चीन से निर्यात, (ख) उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा चीन से निर्यात के संबंध में सूचना है।
156. मौजूदा प्रकटन विवरण याचिकाकर्ताओं के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार नहीं करता है :

157. उत्तर देने वाले निर्यातक / उत्पादक अर्थात् मैसर्स एन्क्यू लू एन फार्मास्ट्रीकल कं. लिमि., झेजियांग कांगले फार्मास्ट्रीकल कं. लिमि., मैसर्स ए एच ए इंटरनेशनल कं. लिमि., झेजियांग केमिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोरपोरेशन और चीन साइनोफार्म इंटरनेशनल कोरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत निर्यातक की प्रश्नावली अपूर्ण प्रकृति की है और उनमें से कोई भी कंपनी ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर (भाग 2) प्रस्तुत नहीं किया है जो निर्यातकों से उनकी क्षमताओं, क्षमता का विस्तार, तीसरे देश को लेने देन वार निर्यात, घरेलू बिक्री, माल भंडार आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहता है। ये व्यौरे निर्यातकों की संभावना संबंधी व्यवहार का द्योतक है और उन्हें निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
158. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जिससे निष्क्रिय क्षमता में वृद्धि हुई है। निर्यातक की घरेलू बिक्री कम हो गई है और भारत को की गई बिक्री में वृद्धि हुई है।
159. आयातों में पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच की अवधि (पी ओ आई) में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। आयातों का पहुंच मूल्य संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत से कम है और आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। शुल्क को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन की तुलना में वृद्धि होगी और पूंजी निवेश पर इसका लाभ नकारात्मक हो जायेगा।
160. इस उत्पाद की घरेलू खपत चीन में कम हो गई है हालांकि इन क्षमताओं को अनुपातिक रूप में कम नहीं किया गया है जो चीन से बाहर उद्योगों के लिए एक खतरा साबित होता है।
161. ए पी आई क्षेत्र को आयातों से संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है और भारत की सरकार भारत में ए पी आई क्षेत्र को फिर से जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 24 सितंबर, 2015 के कटोच समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि ए पी आई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये एक दीर्घ अवधि रणनीति अपेक्षित है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय और अन्य नियामक प्राधिकारों की भूमिका आवश्यक है, इसमें पाटनरोधी शुल्कों का उदारतापूर्वक उपयोग भी अवश्य शामिल होना चाहिए।
162. पूर्व की निर्णायक समीक्षा जांचों में शुल्क को प्रभावी रूप से लगाने के कारण विभिन्न उत्पादकों ने इस देश में नए निवेश किये हैं। लगभग 40.86 करोड़ रुपए और 20000 मी. ट. तक की क्षमताओं के लिए अंतिम संरक्षण के बाद इस उद्योग में निवेश किया गया है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति होगी और ये निवेश खतरे में पड़ जायेंगे।
163. जहां तक कीमत आकर्षकता का प्रश्न है, घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि भारित औसत के आधार पर कोई विश्लेषण कम से कम बहुत अधिक भ्रामक होगा। बिक्री संबंधी प्रत्येक लेन देन हरेक निर्माता द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इसका संबंध किसी अन्य निर्माता से नहीं है। यदि अपेक्षाकृत कम कीमतों पर तीसरे देशों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है तब इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई अनुरोध/ औचित्य नहीं दिया गया है कि क्यों इन बिक्री को भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित नहीं किया जायेगा। उत्तर देने वाले निर्यातकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर तीसरे देशों से को बिक्री करने के लिए न तो किसी बाध्यता को दर्शाया है और न ही कोई अन्य कारण और कारकों का उल्लेख किया है जो उन्हें भारत को उन कम कीमत पर की जाने की वाली बिक्री को परिवर्तित करने से रोकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है चीन के उत्पादक धमार्थ संस्थाएं नहीं हैं और वे व्यापार संगठन हैं जिनका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है।
164. यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत निर्यात कीमत से की जा सकती है। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना करें और उसकी तुलना अलग अलग निर्यात कीमत से करें और उन सभी आयात संबंधी लेन देन में जहां पाटन मार्जिन नकारात्मक है, उसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिये अलग किया जाना अपेक्षित है।
165. कानूनी प्रावधान अतिरिक्त क्षमता का उल्लेख नहीं करते हैं। प्राधिकारी घरेलू और तीसरे देशों के बाजारों के लिए इन निर्यातकों द्वारा किये गये दीर्घकालिन प्रतिबद्धताओं और उनके द्वारा समर्पित क्षमताओं के संबंध में "स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य उत्पादन क्षमता" की जांच कर सकते हैं। घरेलू उद्योग को तीसरे देशों में आपूर्ति के लिए इन निर्यातकों द्वारा किये गये किसी दीर्घकालिन प्रतिबद्धताओं की जानकारी नहीं है और न ही उत्तर देने वाले उत्पादकों ने इस प्रकार के किसी साक्ष्य को रिकार्ड पर लाये हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण, उपयोग में न लाई गई क्षमताएं और सभी निर्यात कम से कम स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य उत्पादन क्षमताओं को दर्शाते हैं और याचिका में तथा लिखित विवरण में इस संबंध में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया साक्ष्य बिना किसी संदेह के यह सिद्ध करता है कि संबद्ध देश से आयातों के कारण संभवतः याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

166. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि निर्यात कीमत का निर्धारण उस कीमत पर जिस पर कीमत पर भारत को इन वस्तुओं का निर्यात किया गया था इस निर्धारण के लिये आधार नहीं हो सकता है।
167. उस कीमत जिस कीमत पर उत्पादक/ निर्यातक भारत को निर्यात कर रहे हैं, में अंतर है। घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि यदि वह कीमत जिस पर उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्रत्यक्ष तौर पर इस उत्पाद का निर्यात किया है और वह कीमत जिस पर इस प्रकार के उत्पादकों ने भारत को अंतर्विगतता निर्यात के लिये व्यापारियों को यह माल दिया है, की तुलना की जाती है। तब यह देखा जायेगा कि उत्पादकों ने इस माल को चीन के व्यापारी को बेचा है जिससे भारत को निर्यात उस कीमत पर किया जा सके जो उस कीमत की तुलना में बहुत ज्यादा कम है जिस कीमत पर व्यापारियों ने भारतीय बाजार में इस उत्पाद की बिक्री की है। इसके अलावा, उत्पादकों ने भारतीय बाजार में बहुत अधिक कीमत पर प्रत्यक्ष रूप से इस उत्पाद का बीजक भी भेजा है।
168. घरेलू उद्योग फिर से इस तथ्य को दोहराता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों को सहयोगी के रूप में नहीं मानना चाहिए क्योंकि ज़ेजियांग कांगले फार्मास्ट्रीकल कं. लिमि., मैसर्स ए एच ए इंटरनेशनल कं. लिमि., ज़ेजियांग केमिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोरपोरेशन और चीन साइनोफार्म इंटरनेशनल कोरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें से किसी भी पक्षकारों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर (भाग 2) का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जो इन निर्यातकों से तीसरे देशों को किये गये बीजकवार निर्यातों के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहता हो। यह सूचना निर्णायक समीक्षा जांच में संभावना के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
169. यह विवरण तीसरे देशों को अलग निर्यात लेन देन में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने में मदद करता है। घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे निर्यातक/ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों को त्रुटिपूर्ण के रूप में माने और उसे असहयोगी के रूप में माना जाये।

ठ. 2 निर्यातक द्वारा किया गया अनुरोध

170. निर्यातक को प्रकटन विवरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

ठ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

171. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से सूचनाओं की प्रति के प्रकटन के संबंध में किये गये अनुरोध के बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया गया है। विरोधी पक्षकार को भेजे गये ई-मेल सहित सूचना का सभी अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।
172. यह अनुरोध किया जाता है कि हमारा मौजूदा प्रकटन विवरण विद्यमान व्यापार कार्यप्रणाली और नियमावली के अनुसार जारी किया जाता है। पाटन और क्षति संबंधी विश्लेषण नियमावली और प्राधिकारी की विगत कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है। प्रत्येक मामले में पाटन मार्जिन नियमावली के अनुसार सभी लेन देन की भारित औसत के आधार पर तय किया जाता है।
173. चीन जन. गण. से निर्यात के संबंध में चीन जन. गण. की सीमा शुल्क संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चूंकि कुल निर्यात का 64 प्रतिशत का निर्यात उस कीमत से अधिक कीमत पर किया गया है जिस पर चीन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत को करता है और इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बाजार अन्य देशों की तुलना में कीमत आकर्षक नहीं है।
174. जहां तक असहयोगी निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमताओं की जांच का प्रश्न है प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में सूचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों और सार्वजनिक डोमेन (क्षेत्र) में उपलब्ध सूचना के आधार पर है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि चीन जन. गण. में व्यापारी अपने वेबसाइट पर उत्पादकों की क्षमताओं को दर्शाते हैं और उनके पास उनका अपनी उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं और इस कारण से उनके वेबसाइट पर उल्लेख की गई क्षमताएं भ्रामक हैं। हालांकि, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों (जिसमें असहयोगी उत्पादक शामिल हैं) के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं से इनकार नहीं करते हैं। यदि चीन जन. गण. के पास अतिरिक्त क्षमताएं भी उपलब्ध हैं तब प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन की संभावना बहुत दूर है क्योंकि भारतीय बाजार अन्य देशों की तुलना में कीमत आकर्षक नहीं है।

175. सहयोगी निर्यातकों का उनकी क्षमता, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री और माल भंडार का ब्यौरा उनके निर्यातक की प्रश्नावली (एन सी वी) में सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराया गया है और संगत शीर्षों के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है।
176. आयातों की मात्रा, पहुंच कीमत और संबंधित मानदंडों के संबंध में विश्लेषण संगत शीर्षों के अंतर्गत किया गया है जो उल्लेख करता है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में 2969 मी. ट. से जांच की अवधि की बाद की अवधि अर्थात् अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में 981 मी. ट. तक गिरावट आई है। संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत की तुलना में अपेक्षाकृत कम पहुंच कीमत के संबंध में यह देखा गया है कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान बिक्री की लागत विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत की तुलना में बहुत कम रही है और इसलिए घरेलू उद्योग के तर्क पर इस संदर्भ में सहमति नहीं हुई है।
177. जहां तक कटोच समिति की रिपोर्ट, 145वीं संसदीय रिपोर्ट और भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, आयुष विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय ज्ञापन जैसे दस्तावेजों में यथाअभिव्यक्त भारत सरकार के दृष्टिकोण का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच नियमावली, मामले के तथ्यों और प्राधिकारी की विगत कार्यप्रणाली के अनुसार की गई है।
178. जहां तक चीन और भारत के बीच दो भागों में बांटे जा रहे वैश्विक उत्पादन और वर्तमान घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में तर्क का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसकी क्षति संबंधी विश्लेषण के अनुसार, घरेलू उद्योग का उत्पादन भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
179. जहां तक संबद्ध वस्तुओं का प्रश्न है, प्राधिकारी द्वारा कीमत आकर्षकता का विश्लेषण भारत को चीन के निर्यातों के लिए कीमत आकर्षक के रूप में नहीं रखता है।
180. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किये गये अन्य अनुरोधों का समाधान पहले ही संगत शीर्षों के अंतर्गत किया जा चुका है।

ठ. निष्कर्ष

181. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में रिकार्ड किये गये अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, प्राधिकारी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि -
 1. रिकार्ड पर साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि चीन जन. गण. से पाटित आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
 2. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात क्षति की पूरी अवधि के दौरान मामूली स्तर पर बना रहा है और जांच की अवधि की बाद की अवधि में इसमें कमी आई है।
 3. घरेलू उद्योग ने क्षति संबंधी सभी मानदंडों के मामले में सुधार दर्शाया है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
 4. जहां तक संबद्ध वस्तुओं का प्रश्न है, प्राधिकारी द्वारा कीमत आकर्षकता का विश्लेषण भारत को चीन के निर्यातों के लिए कीमत आकर्षक के रूप में नहीं रखता है और इस कारण से इस बात की बहुत कम संभावना है कि चीन जन.गण. से निर्यात पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारत की ओर परिवर्तित हो जाएगा।
 5. पाटनरोधी शुल्क सितंबर 2001 से लागू था और घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क ने अपने अभिष्ट उद्देश्य को पूरा कर लिया है।

ड. सिफारिश

182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच आरंभ की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों/ आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था जिससे कि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलू पर संगत सूचना उपलब्ध करा सकें। पाटनरोधी अधिनियम और

नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के बाद पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन की संभावना की जांच शुरू किये जाने और उसे आयोजित किये जाने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप ऊपर में दिये गये कारणों और/ अथवा विश्लेषण के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी। इस कारण से प्राधिकारी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: 3rd Sunset Review Investigation (SSR) concerning imports of Paracetamol originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 7/16/2018-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Paracetamol” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).
2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 60/1/2000 – DGAD dated 30th January, 2001. The Preliminary Findings were issued by the Authority vide Notification No. 60/1/2000-DGAD dated 16th April, 2001 and the provisional antidumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 89/2001 Customs dated 6th September, 2001. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 60/1/2000-DGAD dated 22nd January 2002, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notifications No. 29/2002 Customs dated 27th March, 2002 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. 1st Sunset Review was concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 15/20/2006-DGAD dated 23rd July 2007 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 99/2007 -Customs dated 3rd Sept, 2007. 2nd Sunset Review was concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 14/1009/2012-DGAD –dated 26th August 2013 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No 26/2013-Customs dated 28 October, 2013. A 3rd Sun set review investigation was initiated on 24th May 2018 and Final Findings was issued by the designated authority vide Notification No 7/16/2018-DGAD dated 29.01.2019 wherein the authority recommended not to continue the existing anti-dumping duty imposed upon the imports of Paracetamol from China PR. Thereafter, Special Civil Application No 5278 OF 2019 was filed in the High Court of Gujarat challenging the impugned Final Findings and disclosure statement issued by the designated authority on 29.01.2019 and 15.01.2019 respectively in the 3rd Sunset Review Investigation. The Hon’ble High Court of Gujarat in its judgment dated 3rd July, 2019 ordered to remand back the case for reconsideration by the Designated Authority.
3. Whereas, in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the anti-dumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Whereas, the petition was filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited (hereinafter referred to as Petitioners) and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s

Granules India Ltd., and M/s Meghmani Unichem LLP in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of sunset review investigation of the Anti-Dumping Duty concerning imports of Paracetamol originating in and exported from China PR.

6. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority issued a Notification. No. 07/16/2018-DGAD dated 24th May, 2018, published in the Gazette of India, initiating a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 24th May 2019 vide Notification No. 39/2018-Customs (ADD) dated 20th August, 2018 which was later extended up to 27th October, 2019 vide notification No. 27/2019-Customs (ADD) dated 12th July, 2019.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. GENERAL PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 24th May, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating Sunset Review investigation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Paracetamol originating in and exported from China PR
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days from the date of communication in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).
 - iv. The Authority provided copy of the non-confidential version of the application to the known exporters/producers and the embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the form of a public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules:
 - a) Anhui Bayi Chemical Industry Co. Ltd.
 - b) Anhui Fubore Pharmaceutical
 - c) Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co.
 - d) M/s Wenzhou Pharamaceuticals factory
 - e) Changshu Huagang Pharmaceutical Co. Ltd.
 - f) Hebai Jiheng Group Co. Ltd.
 - g) Jiangsu World Kindly Pharmaceuticals Ltd
 - h) Jiangsu Guoheng Pharma Chemical Co. Ltd.
 - i) Shanghai Bailion Chemicals Co. Ltd.
 - j) Lianoyuan City Baikang Pharmaceutical
 - k) Runqi Trading Co. Ltd.
 - l) AnqiuLu'an Pharamaceutical Co Ltd
 - vi. The following producers/exporters have filed the Exporter questionnaire response.
 - a) M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - b) M/s A.H.A International Co., Ltd.

- c) China Sinopharm International Corporation
 - d) Zhejiang Chemcials Import and Export Corporation
 - e) Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - f) Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - g) Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.
- vii. Supplementary questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the authority within the prescribed time limits.
- viii. However, none of the exporters have filed the Supplementary questionnaire.
- ix. The Authority sent a copy of the Initiation Notification along with Importer's Questionnaires to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4).:
- a) Aura Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
 - b) Shalina Laboratories Pvt. Ltd.
 - c) Medicamen Biotech Ltd.
 - d) Adcock Ingram Ltd.
 - e) Sanofi India Ltd.
 - f) Fourrts (India) Laboratories Pvt Ltd.
 - g) Indoco Remedies Ltd.
 - h) Astra Lifecare (India) Pvt. Ltd.
 - i) J.B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
 - j) Unilink Pharma Pvt. Ltd.
 - k) Medopharm
 - l) Milan Laboratories (India) Pvt. Ltd.
 - m) Agog Pharma Ltd.
 - n) Combitic Global Caplet Pvt. Ltd.
- x. However, no questionnaire response has been received from any importer of the subject goods.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules
- xiii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the Non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. Period of Investigation in the present investigation is 01st April 2017- 31st March 2018. The injury investigation period is April 2014-March15, April 2015-March16 and April 2016-March17 and the Period of Investigation (POI).
- xv. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) & DG Systems. The Authority has relied on DGCI&S data and the data of co-operative exporters for calculating volume and value of imports of the subject goods in India.

- xvii. The Authority held oral hearing on 6th August 2018 to provide an opportunity to all the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). The interested parties who had presented their views in the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by the opposing interested parties. The Authority has considered submissions received from all the interested parties appropriately. Post remand back oral hearing was held on 19th August 2019 and accordingly the interested parties filed their written submissions and rejoinders which were duly considered by the Authority.
- xviii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
- xix. *** in this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 65.33

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

B.1 Submissions by the Domestic Industry

9. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:-
- The scope of the product under consideration under the present investigation is "Paracetamol also known as acetaminophen" as determined by the Authority in previous investigations. Paracetamol is an organic chemical and is classified under Custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
 - Paracetamol is a white powder. Its chemical formula is C₈H₉NO₂. Paracetamol is a common analgesic and antipyretic drug that is used for the relief of fever, headache and other minor aches and pains. It is a major ingredient in numerous cold and flu medications and many prescription analgesics.
 - The present investigation being a Sunset Review investigation and antidumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority should consider that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the earlier investigations.

B.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

10. None of the other interested parties have raised any issues with regard to the product under consideration.

B.3 Examination by Authority

11. The product under consideration in the present Sunset Review investigation is Paracetamol. Paracetamol is classified under Customs sub heading No 2922.2933 under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.
12. The Product under consideration as defined in the previous investigations is as follows :-
- "The product under consideration, in the original as well as the 1st SSR investigation and the present sunset review investigation, is "Paracetamol also known as acetaminophen", originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation as well as the 1st SSR investigation".*
13. The present investigation being a Sunset Review investigation and antidumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the earlier investigations. Moreover, none of the interested parties have made any submission in this regard.
14. Therefore the authority has considered PUC as under :-

The product under consideration, in the previous investigations as well as the present sunset review investigation, is "Paracetamol also known as acetaminophen", originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

"Paracetamol is an odourless white crystalline powder. Its chemical formula is C₈H₉NO₂. Paracetamol is a bulk pharmaceutical active ingredient, displaying analgesic and antipyretic properties. It is used in a number of Rx and OTC drug formulations in the form of powders, granules, injectibles and tablets. Paracetamol is an organic chemical and is classified under Custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."

C. LIKE ARTICLE**C.1 Submissions by the Domestic Industry**

15. The domestic industry has claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications and tariff classification etc.

C.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

16. None of the interested parties have disputed the claims made by the domestic industry in this regard.

C.3 Examination by Authority

17. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the Domestic Industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority had examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigations, which mutatis mutandis is relied upon in the present review investigation. The goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1 Submissions by the Domestic Industry**

18. The domestic industry has made the following submissions:-

- i. The Petition for review and continuation of the anti-dumping duty in force on imports of Paracetamol originating in or exported from China PR has been filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s Granules India Ltd., and M/s Meghmani LLP.
- ii. The Petitioners other than M/s Sri Krishna pharmaceutical have not imported the product under consideration. M/s Sri Krishna pharmaceuticals Ltd have imported merely 30 MT, which is insignificant in relation to its production, Indian production and Indian demand.
- iii. Petitioners command a major proportion in Indian production and accordingly constitute “domestic industry” within the meaning of the Rules.
- iv. Petitioner is not related, either directly or indirectly, to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus, the petitioner is an eligible Domestic Industry under Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

19. The interested parties have made the following submissions:-

- i. The levy of the anti-dumping duty is dependent upon the dumping margin and there is no such principle of granting sufficient protection to the domestic industry in the anti-dumping investigations.
- ii. There are significant changes in the composition of the domestic industry in all the four investigations concerning the product under investigation before the Authority as may be seen from the following:-
 - a) Original Investigation: It may be seen that in the original investigation before the Authority, there were four producers namely M/s Triton Laboratories Ltd., M/s Vamsi Labs Ltd., Srinivasa Agro Industries & Drugs Ltd. and Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. who participated in the investigation and provided injury information.
 - b) First Sunset Review: In first sunset review there were three producers namely, Sri Krishna Pharmaceuticals, M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd and M/s Bharat Chemicals ltd.
 - c) Second Sunset Review: In the second SSR, Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Bharat Chemicals Ltd. provided injury information.

- d) Third Sunset Review-Present Investigation: In the current investigation, again only the 2 producers namely Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd. have been participating and provided injury information.
- e) The composition of the domestic industry or the domestic producers in all the four investigations are different and it is not difficult to assume that the composition of the domestic producers was changed at their will and desire to suit their needs,
- f) It may be seen that the domestic producers who were petitioners in the previous investigations i.e. original investigation and the two sunset review investigations have not provided any information in the present case
- g) There is no analysis or reasons in the petition as to why those producers who were petitioners in the earlier investigations are not providing information in the current investigation.
- h) In the initiation notification also, there is no analysis with respect to those producers not providing information.
- i) M/s Triton Laboratories Ltd. was merged with Granules India Ltd. in the year 1998. However, M/s Triton Laboratories Ltd. was projected as a separate company from Granules India Ltd. In spite of the fact that the former was merged with the later at the time of initiation of original investigation i.e. on 30th January 2001 and no company with the name of Triton Laboratories existed at the time of initiation of original investigation. However, the domestic producers forming part of the domestic industry at the time of original investigation misled the Authority and got the anti-dumping duties imposed by misrepresenting the facts in the original investigation.
- j) M/s Granules India Ltd. in the first sunset review investigation was shown as an importer and not included as part of the investigation. M/s Granules India Ltd. is the largest producer of subject goods in India. It has sales of Rs. 579 Crores in the POI
- k) The domestic industry has not provided the injury information of M/s Granules India Ltd despite it being the largest company.
- l) Even in the previous two sunset reviews investigations, no injury information was obtained from M/s Granules India Ltd. for a meaningful analysis and conclusions in those investigations. There are no reasons in the petition or in the initiation notification as to why this producer has not provided information in the present investigation when the amalgamated company of Granules India i.e. Triton Laboratories participated in the original investigation as a petitioner and provided injury information.
- iii. M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd. is also one of the largest producers of the subject goods in India. It was a petitioner in the first sunset review and not a petitioner in the second sunset review. With regard to this producer also, there are no reasons in the petition or in the initiation notification as to why this producer has not provided information in the 2nd sunset review and is now providing injury information in the present investigation.
- iv. The producers who were also the petitioners in the previous investigations commanding majority of the production have not provided injury information in the current investigation and only the producers with a limited and low share in the total domestic production have provided injury information, there is no ground for the continuation of the duties in the current investigation as in each investigation the sufficient injury information of the domestic industry has been kept away from the examination.
- v. The present case is a fit case for termination of investigation and discontinuation of the duties.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

21. The petition has been filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s Granules India Ltd., and M/s Meghmani LLP. Post initiation, one of the supporting companies namely M/s Bharat Chemicals has provided all the necessary information. However, the Authority has not considered the same as it was filed at belated stage of investigation.
22. In the present case, the producers before the Designated Authority have output constituting a major proportion of the total domestic production and thereby the legal requirement as stipulated in Rule 2 (b) of the AD rules is met. However, in

case of Sunset review it would be desirable to have the same composition of domestic industry as in original investigation.

23. The Authority notes, on the basis of information on record that the production of Applicants constitutes a major proportion of total Indian production. Among the petitioners M/s Sri Krishna pharmaceuticals Ltd. has imported merely 30 MT of PUC during POI, which is 0.45% in relation to its production and 0.06% in Indian demand, which is very insignificant and therefore the Authority has considered them as an eligible domestic industry while initiating the present investigation. Also, the Authority had satisfied itself of the adequacy and accuracy of the data submitted by the petitioner by an onsite visit. Further, the petitioners are related neither to an importer in India nor to any exporter from subject country. Thus, the petitioner companies are eligible domestic industry in terms of AD Rules. Further, production of the petitioner companies constitutes “a major proportion of total Indian production” and hence, satisfies the standing requirements for the subject goods under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by the domestic industry

24. The domestic industry has made the following submissions:-
- i. The exporter/ producers have made unnecessary claims as to confidentiality or provided incomplete information thereby handicapping the domestic industry in making meaningful comments with regard to the responses filed. The responses are not properly indexed or summarized.
 - ii. Information provided in non-confidential version is beyond understanding. The NCV does not provide clear understanding of the data and the domestic industry is unable to provide detailed comments on that for the same reason.
 - iii. Non-confidential version of the questionnaire responses is grossly inadequate and incomplete. The concerned interested party has not disclosed all such information that they are obligated to disclose under the Rules and practice being followed by the Designated Authority in this regard.

E.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

25. The exporters/importers/other interested parties have made the following submissions:-
- a. The petitioners have claimed excessive confidentiality without providing any legitimate reasons in violation of Rule 7 of the Customs and Tariffs Rules, 1995. The Petitioners have not disclosed the following information in their petition:-
 - b. Soft Copy in excel file of transaction-wise and sorted import data, raw/original import data and list of excluded transactions from DGCI&S has not been provided.
 - c. The import data has not been provided for the whole POI and has been provided only for the 9 months.
 - d. The item-wise details of constructed normal value have been kept as confidential,
 - e. Company-wise production details of the petitioners, supporting producers and the domestic producers have been kept as confidential.
 - f. The annual report of the companies for the POI and the previous three years have not been provided. The domestic industry has simply stated that the same may be seen from the website of the petitioners. However, it may be seen that there are no annual reports available on the website of the petitioners.
 - g. In the application, it has been mentioned that Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. has imported the subject goods. However, the reasons have not been provided by the domestic industry.
 - h. The domestic industry has claimed adjustment from export price for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland transportation, commission and VAT adjustment. However, no evidence with regard to the aforesaid adjustments claimed have been provided by them,
 - i. Profit/ loss and ROCE in percentage terms have been kept confidential,
 - j. The Hon'ble Authority may kindly direct the petitioners to disclose and provide the aforesaid information so as to enable the exporters/ producers for making effective comments in this investigation.

E.3 Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

“7. Confidential information:-

(1) Notwithstanding anything contained in sub rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

27. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the need for treating them as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims of all the parties and accordingly not disclosed such information to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential summary of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file.

F. Miscellaneous Submissions

F.1 Submissions by the domestic industry

28. The exporter questionnaire filed by responding exporter/ producers namely M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd., Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd, M/s A.H.A International Co., Ltd., Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation, and China Sinopharm International Corporation are deficient in nature and none of them have filed the exporter Questionnaire Response (Part2), which seeks information from the exporters on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, inventories etc. These details/information are indicative of likelihood behaviour of the exporters and therefore they are required to be submitted to the Authority in the Sunset Review investigation. It is submitted that, this is not a case of deficient information but complete failure to file the required information in the prescribed format itself.
29. The production of product under consideration is quite limited globally. As, about 86% of global production is in India and China only and out of which 62% of the production is in China alone, while India commands the remaining 24%. Thus, any sickness in this industry would leave the Indian users at the mercy and monopoly of the Chinese producers.
30. That due to the adverse effect of the insufficient form of duty there were large-scale production suspension in the country, which was primarily in the last two decades (all these closures are more than 5 years old and are prior to previous extension of ADD).
31. As per 145th Parliamentary standing committee on commerce which assessed the impact of Chinese goods on Indian industry, it is clearly stated that API sector needs protection from import and the government of India also endeavors to revive the API sector in India.
32. Katoch Committee Report dated 24 September, 2015 on Active Pharmaceuticals Ingredients (APIs) specifically states that a long term strategy for strengthening API sector by involving Ministry of Commerce as well as other regulatory authorities is required which involves judicious and liberal use of measures like anti-dumping.
33. FICCI report February 2018 edition on “Trends and Opportunities for Indian Pharma” highlights that dependence on China for API supplies exposes the pharma industry to raw material supply disruptions and price volatility.
34. Office Memorandum dated 18 April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, constituted a Task force to formulate a roadmap for enhanced production of API s in the country as there is need for concerted efforts to harness the opportunities in pharmaceutical sector.
35. The public at large is already well protected through a regulatory mechanism as Paracetamol is covered under National List of essential medicine in Pharmaceutical Policy, 2015.
36. Paracetamol is one of the cheapest API available in the country.

F.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

37. None of the other interested parties has made any submissions.

F.3 Post remand back submissions made by the Domestic Industry and the exporters.

Repetitive submissions by the interested parties have not been repeated for the sake of brevity.

a) Submissions by Domestic Industry

38. It is submitted by the Domestic Industry that in the previous final findings with regard to the majority of exports under advance license scheme, both the petitioners and the opposing parties agree that exports from subject countries in this period have occurred only under advance license scheme.
39. Imports to India have occurred under the duty exemption scheme, the importers have not paid either anti-dumping duty or basic custom duty. Since no taxes and duties were payable on these imports, therefore the price reported to Indian Customs were abnormally high, as there was no adverse impact of quoting Higher Price.
40. Since the imports have occurred under the duty exemption scheme, The DI submits that the export price reported to Indian Customs during that period are unreliable. The DI therefore requests the authority to consider the price at which material was sold by the producers to unrelated traders in the domestic market
41. The DI further submits that the present exports under duty exemption category establishes that these are not the real prices at which the Chinese producers would export the product. It is the third countries lower prices that are representative of the exporter's real prices for the Indian market.
42. The behavior of the exporters have changed post issuance of final finding. Even when the order had not even attained finality the Chinese producers and Indian importers resorted to significant imports of products at materially low prices.
43. The production of Product under Consideration (PUC) is quite limited globally. About 86% of the global production is in China and India out of which China and India commands for 62% and 24% of the shares respectively and any sickness in this industry would leave the global demand only at the mercy and monopoly of the Chinese producers.
44. A bare perusal of the exporter's questionnaire filed by the exporters establishes that there is a need for the continuation of duty as it states that there is a decline in capacity utilization of exporter giving rise to the idle capacity. Domestic sales of the exporter has come down and sales to India has increased. The exporters are selling PUC at the rate of 107.71 CNY/KG in their domestic market and they are selling the same in India at 88.18 CNY/KG, which shows dumping.
45. With regard to injury the DI states that the imports have increased in absolute terms in the period of investigation as compared to the preceding two years. The landed price of import is below the cost of production for the subject goods and the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The cessation of duty will lead to an increase in imports in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India and the DI will suffer losses and its return on capital employed would become negative.
46. The DI submits that they are seeking extension of duty on the grounds of likelihood of recurrence of injury.
47. Despite the positive dumping margin and price underselling, India is a much more price attractive market as compared to the other markets.
48. The Chinese producers concede that their domestic consumption for the product has declined. The capacities have not been proportionately reduced thus threatening industry outside China.
49. As per 145th Parliamentary standing committee on commerce which assessed the impact of Chinese goods on Indian industry, it is clearly stated that API sector needs protection from import and the government of India also endeavors to revive the API sector in India.
50. Katoch Committee Report dated 24 September, 2015 on Active Pharmaceuticals Ingredients (APIs) specifically states that a long term strategy for strengthening API sector by involving Ministry of Commerce as well as other regulatory authorities is required which involves judicious and liberal use of measures like anti-dumping.
51. FICCI report February 2018 edition on "Trends and Opportunities for Indian Pharma" highlights that dependence on China for API supplies exposes the pharma industry to raw material supply disruptions and price volatility.
52. Office Memorandum dated 18 April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, constituted a Task force to formulate a roadmap for enhanced production of API s in the country as there is need for concerted efforts to harness the opportunities in pharmaceutical sector.
53. After the effective imposition of duty in the previous Sunset Review investigations, the various producers have made fresh investment in the country. A total of about Rs.40.86 Crores and capacities by 20000MT has been invested in this industry after the last protection. Cessation of anti- dumping duty will cause injury to the domestic industry and these investment will be jeopardized.
54. The Paracetamol industry constitutes small companies which are highly vulnerable and price sensitive. In the past various Paracetamol producers were forced to suspend production as they were unable to compete with the low price imports. Therefore the cessation of duty makes the domestic industry vulnerable.

55. The public at large is already well protected through a regulatory mechanism as Paracetamol is covered under National List of essential medicine in Pharmaceutical Policy, 2015.
56. Paracetamol is one of the cheapest API available in the country
57. The period for which duty has been in force has no relevance under the law to determine whether the antidumping is required to be extended for a further period or not. The real test of extension of duty is whether the injury to the domestic industry is likely to recur in the event of cessation of antidumping duty and not the period for which the duty is levied.
58. The Domestic Industry also request the Designated Authority to compare the price at which the responding producers have directly exported the product and the price at which such producers have given the material to the traders for eventual export to India. Petitioners' understanding is that the producers have sold the material to a price materially lower than the prices at which the traders have sold the product in the Indian market. Further, the producers have also directly invoiced the product to Indian market at higher prices. Just for illustration purposes, if the producers have invoiced the product to India @ US\$ 100 per unit, they have invoiced to the traders @ US\$ 75 and the traders have invoiced the goods to India at US\$ 105. Thus, even when the producers are aware of Indian customers/consumers and have allegedly sold the product at higher prices in Indian market, they have sold the product at lower prices to the traders. DI submit that the price at which the producers have sold the product to the traders are the real prices at which the business has happened in this period.
59. The DI states that the designated authority in its earlier final findings 29th January, 2019 has already held that there are surplus capacities in China PR and the Chinese producers are export oriented and same is herein relied upon.
60. The DI has stated that any analysis on the basis of weighted average is at the least highly misleading. Every sales transaction is made independently by every manufacturer and on standalone basis. If there are significant exports made to third countries at lower prices, there is no submission/justification by these interested parties why those sales would not be diverted to Indian market. The responding exporters have neither shown any compulsion nor any other reason for selling at lower prices to third countries and factors which would prevent them from diverting those low priced sales to India. The Chinese producers do not appear to be charitable institutions and are business organizations whose objective is to maximize the profits.

b) Submissions by the exporters/importers/other interested parties

61. It is submitted by the exporters that the domestic industry is making the contradictory submissions. On the one hand, the domestic industry is alleging dumping and likelihood of dumping on the basis of imports of the subject goods from China and on the other hand, they state that the imports from China are imported at a higher price under advance license and therefore, the imports are not reliable. It is submitted that the domestic industry has not produced any evidence on record in support of their submissions and therefore, there is no merit in the submissions of the domestic industry. With regard to the imports of the subject goods under duty free schemes, it may be seen that for the demand of the subject goods for the exported Paracetamol formulations may in all likelihood will be met from the imports from China due to superior quality of imports and such imports will continue to be made as these imports will not be subject to anti-dumping duty. Thus, considering the nature of the product and the prevailing circumstances, the imports of the subject goods into India will remain imminent to that extent.
62. The domestic industry has not provided the source of information of imports provided for the period April 2018- March 2019 .Even on the basis of the information so supplied, it may be seen that there is no merit in their submissions as the previous final findings in the investigation were issued on 29th January 2019 and the Customs Notification for withdrawal of duties was issued on 16th April 2019 and the duties even continue today in view of the orders of the Hon'ble Gujarat High Court and have not been discontinued. It may be seen that the position that was prevailing before the issuance of the above final findings remains the same even after the issuance of the above final findings. Therefore, there is no merit in the submissions of the domestic industry that imports post issuance of final findings have increased.
63. There are no significant changes in the capacity utilization of Hebei Jiheng and it has remained more or less in the same region throughout the injury investigation period. With regard to sales also, it may be seen that the same is more or less the same throughout the injury investigation period. For the selling prices, it is submitted that the domestic prices and the exports to India throughout the injury investigation period are comparable. It may also be seen that the imports of the subject goods to India by Hebei Jiheng are not so significant for drawing any conclusion on the basis of their imports. It is also submitted that the transaction-wise details of export to other countries by the exporters represented by us have already been filed and are a matter of record.
64. Indian market is not price attractive for the exporters as the prices charged by them for the other countries on average basis are higher than the Indian prices.
65. No significant changes in the demand of the PUC in China or other countries and remain more or less the same throughout injury period investigation.

66. In anti-dumping investigation the decision for the levy of duties is dependent upon the dumping or likelihood of dumping and injury and it has no connection with the investment made by the domestic industry in the capacity expansion. The designated authority held the same in the Melamine SSR Investigation from EU, Indonesia, Iran and Japan
67. The consideration of the public interest is not a legal condition to be examined in accordance with Indian law on anti-dumping for the continuation, imposition or withdrawal or termination of the duty or investigation.
68. It is reiterated by the exporters that in the cases of Dry Cell Batteries from China PR (Case No 15/12/2011-DGAD & Final Findings dated 20th May 2013) it was held by the Authority that the anti-dumping duties beyond 10 years be imposed in special cases only. The present case is not a special case where duty is required to be continued. The duties for the PUC has been in existence for the past 17-18 years.

F.4 Examination by the Authority

69. Imports under advance licenses are not meant for domestic consumption and therefore it has no bearing on the prices of domestic industry and consequential likelihood of injury.
70. As regards the continuation of duty beyond a period of 17 years, the Authority finds that the duties have been extended in the past only when it was found after investigation that there was likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of duty.
71. As regards the submission that 86% of global production is in India and China out of which 62% of the production is in China and 24% in India therefore any sickness in the industry would leave the Global demand at the mercy and monopoly of Chinese producers, it is stated that only 6% of the Indian demand is being met by the imports and Domestic Industry is operating efficiently.
72. From the analysis of DGCIS import data it is seen that imports have reduced from 2969 MT in the POI to 988 MT in the post POI and the landed value of the imports in the Post POI has increased to Rs. 362/Kg from Rs. 250 /Kg in the POI.
73. As regards the capacity utilization of the cooperative exporters is concerned it is noted that the capacity utilization of the major exporter who has exported 80% of the total exports from the cooperative producers of China has increased from 68.7% in year 2016-17 to 71% in the POI.
74. As far as the price attractiveness of the India is concerned, the Authority has analysed the China PR custom data with regard to export from China PR to the rest of the world which indicates that 28.6 % of total volume of exports to third countries is at a price lower than the price at which China exports to India. Whereas 64.1% of the total exports are priced at rates higher than the prices at which China exports the subject goods to India.
75. As regards the submission that the price at which the producers have sold the product to the traders are the real prices at which the business has happened in this period, it is stated that the real prices are the prices at which China country as a whole has exported to India for which landed value has been calculated at USD 3828/MT which is higher than the Non-injurious price of the domestic industry and not the prices at which producers have sold product to traders in China PR.
76. The Authority takes note of the submissions filed by the Applicants as to the stance of Government of India with regard to API and other market information such as the report of FICCI.
77. Dumping analysis has been detailed under the relevant headings.
78. Other submissions made by the interested parties have been examined under the relevant headings.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

79. The Authority sent questionnaire to known exporters from subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers and exporters from the subject country filed the questionnaire response:-
 - i. M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - ii. M/s A.H.A International Co., Ltd.
 - iii. China Sinopharm International Corporation
 - iv. Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation.
 - v. Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vi. Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vii. Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.

80. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means: -

"comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin".

G.1 Views of the Domestic Industry

81. The following are the submissions made by the domestic industry, during the course of present investigation and considered relevant by the Authority:-

- i. China needs to be treated as non-market economy for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
- ii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- iii. The imports are entering the Indian market at dumped prices.
- iv. There is difference in prices in different import transactions which mean that Chinese producers are selling very same product at a price which differs significantly even at the same time period and is not a peculiar phenomenon of POI, but extends to the entire injury period,
- v. It is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price. The Designated Authority is, therefore, requested to compute the weighted average normal value and compare the same with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same are required to be excluded for determination of dumping margin.
- vi. There can be no plausible reason/justification for such significant difference in the prices in respect of imports being reported at the same time.

G.2 Views of the other interested parties

82. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties are as follows:-

- i. Determination of the normal value for subject country in the current investigation as computed by the domestic industry is not in accordance with the legal provisions and therefore, the determination of dumping margin in the current investigation by the petitioners is flawed.
- ii. Normal value for the companies in China PR in the current investigation may please be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods.
- iii. It is in view of the fact that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15 (d) and has become non-operational.
- iv. At present, no provisions which enable the Hon'ble Authority for considering Chinese producers as operating on non-market economy principles for disregarding their domestic prices and costs and the normal value for China may be determined on the basis of their domestic prices and cost of the subject goods.
- v. Any other methodology used for the determination of normal value for Chinese exporters would be in violation of the obligations of India under the WTO.

- vi. Without prejudice to above submission it is submitted that determination of normal value for Chinese exporters on the basis of their records without following any additional procedure, domestic industry has arbitrarily determined the normal value for Chinese exporters without following the due procedure as laid down under the Indian Anti-dumping Rules.
- vii. The constructed normal value proposed by the domestic industry is based on the cost of production in India and considering the rate of profit at 5%. However, the item-wise cost details of the constructed normal value have not been provided.
- viii. The methodology of relying upon the Indian costs and prices is to be followed only when it was not possible to construct the normal value on the basis of other alternatives prescribed in the opening sentence of Para 7.
- ix. In terms of the provisions of Para 7, the market economy third country is required to be first identified for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, the normal value can be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
- x. The domestic industry is under obligation to inform, without reasonable delay the selection of market economy third country to the parties concerned so as to provide an opportunity to respond to the same.
- xi. Mandatory procedure prescribed by the law has not been followed, as the interested parties have not been put to notice about selection of the third country. Nor have the interested parties been requested to suggest and make necessary information available about the third country.
- xii. In the absence of following the mandatory procedure, the present proceeding cannot continue in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC).
- xiii. The failure to follow the mandatory procedure of Para 7 has substantive implications on the determination of the normal value and resultantly the dumping margin.
- xiv. Therefore, the Hon'ble Authority is requested to follow the procedure prescribed in Para 7 of the Annexure I in the current investigation.

G.3 Examination by the Authority

a. Normal Value in China

- 83. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of normal value. The Authority sent copies of the Supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the AD Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers filed any response to the Supplementary questionnaire issued by the Authority.
- 84. Accordingly, the normal value and export price for the all the producers/exporters from the subject country have been determined as below:-

b. Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

- 85. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of Anti-Dumping Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in Para 7 of Annexure I of the AD rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "any other reasonable basis".
- 86. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses. Accordingly, the constructed normal value for Chinese exporters is determined **Rs. ***per Kg.**

c. Determination of export price of China PR

- 87. The Authority notes that below mentioned exporters from China PR have furnished information to the Authority, which was used for determination of export price and individual dumping margin.
 - i. M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - ii. M/s A.H.A International Co., Ltd.
 - iii. China Sinopharm International Corporation
 - iv. Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation
 - v. Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.

- vi. Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
- vii. Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.

88. In view of the responses filed, the Authority has analyzed the response made by the producers/exporters as follows:-

a) M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd. (producer) and M/s A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation.

89. The Authority notes that M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd. has exported *** MT of the subject goods directly to India and ***MT through its traders M/s A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation. The Authority notes that whereas Anqiu Lu An Pharmaceutical Co. has reported an export price of US\$ ***/MT and A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation have reported net export price of US\$ ***/MT, US\$ ***/MT and US\$ ***/MT respectively.

90. The producers-exporters have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, and marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. Ex-factory export price has been determined for each producer/exporter. Weighted average export price of the said producer and its respective traders have thereafter been determined as US\$ ***/MT considering the total volume of exports made by the said exporter.

b) M/s Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd. (Producer) and M/s Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.

91. The Authority notes that M/s Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co. has exported *** MT through its trader namely M/s Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd. They have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, and marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. After adjustment of the expenses claimed by the producer/trader, the authority has determined the ex-factory export price as US\$ ***/MT.

c) M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd...(Producer).

92. The Authority notes that M/s Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd have exported *** MT directly to India. The exporters have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, and marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. After adjustment of the expenses claimed by the producer/trader accordingly, the authority has determined the ex-factory export price as ***US\$/MT.

93. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the subject country has been determined as provided in the table below:-

G.4 DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Name of company (Producer) (POI)	Name of the company (Exporter)	CNV US\$/MT	NEP US\$/MT	Dumping margin US\$/MT	DM%	Range
M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	M/s A.H.A International Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
	China Sinopharm International Corporation					
	Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation					
Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-(10)
Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.		***	***	***	***	10-20

- (a) Comparing the normal value and export price at ex-factory level for the country as a whole, the dumping margin for the subject country is determined as below:-

Particulars US\$/Kg -Rs./Kg (POI)	US\$/Kg	Rs./Kg
Normal Value	***	***
Net Export Price	***	***
Dumping Margin	***	***
Dumping Margin %	***	***
Range %	10-20	10-20

H. INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions by the Domestic Industry

94. Followings are the submissions made by the Domestic Industry: -

- i. Nature of sunset review is different than that of original investigation as the focus is more on likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, in case antidumping duties are removed. Presence of current injury or presence of current dumping is not required to be examined for the review cases where likelihood of injury is more important.
- ii. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry is expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in force.
- iii. The assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic industry.
- iv. The Designated Authority has to address the question as to whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.
- v. There is negative price undercutting. This is due to anti-dumping duty in force; the situation is likely to reverse in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vi. There had been an increase in selling price and the landed price of imports due to anti-dumping duty in force. In the event of cessation of anti-dumping duty, the imports in all likelihood would have price suppression and depression effect.
- vii. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased. However, should the present duties cease at this stage, the capacity utilization shall decline significantly.
- viii. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have increased since the base year.
- ix. Market share of the domestic industry and other Indian producers has remained constant throughout the investigation period. In the event of cessation of anti-dumping duty, the dumped imports from subject country will resume in significant volumes taking away market share of the domestic industry.
- x. The growth of the domestic industry in terms of most of the parameters has shown improvement. This is due to anti-dumping duty in force. The situation is likely to reverse in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xi. In the present case, export price from subject country significantly differs in terms of time period and therefore it is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price.
- xii. The Designated Authority is requested to consider weighted average normal value and compare with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same are required to be excluded for determination of dumping margin.
- xiii. The period for which duty has been in force is irrelevant for determining whether there is a need for continuation of duties. The law provides for extension of duties if the cessation of such duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury. Even as per the practice of other countries such as Canada, USA, Brazil and European Union, duties may continue to be in force for more than 15 years, even if there are no imports of the subject goods.

H.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

95. Followings are the submissions made by the exporters.

- i. There is no injury to the domestic industry in the current investigation and all the injury parameters of the domestic industry have significantly improved over the injury investigation period.

- ii. The anti-dumping duties against the import of subject goods are in existence for more than 17 years and the present case is not a special case where duties are required to be extended for a further period of 5 years.
- iii. The majority of imports to India from subject country are under duty free schemes such as advance license, DEPB etc. run by the Govt. of India which are not subject to duty.
- iv. Even if such imports are included for analysis of injury and likelihood of injury and anti-dumping duty is recommended, the imports made under said duty free schemes would not be subject to any anti-dumping duty and would continue to come to India
- v. The composition of the domestic industry in all four investigations before the Hon'ble Authority has significantly changed. Therefore, there are no reasons to believe that the domestic industry is being currently affected.
- vi. The largest producer of the subject goods i.e. Granules India having sales of Rs. 579 Cores in the period of investigation in India have been abstained from all the 3 sunset review investigations and provided no injury information. Therefore, the analysis of injury and likelihood of injury on the basis of limited information in all the 3 SSR investigations cannot give the true picture of the state of the domestic industry and therefore, in the current case, there is no need to extend duty for another period of five years.
- vii. The Authority while issuing the Final Finding concerning Dry Cell Batteries from China PR (Case No. 15/2/2011-DGAD & Final Findings dated 20th May 2013) has held that the anti-dumping duties beyond 10 years be imposed in Special cases only.
- viii. In case there is increase in imports from subject country after the anti-dumping duty is not extended, the domestic industry can always file application for initiation of fresh anti-dumping investigation.

H.3 Examination of the Authority

96. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
97. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules.
98. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
99. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
100. In consideration of submissions received in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

(i) Assessment of Demand/ Apparent Consumption

101. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand for the product under consideration is given below:-

*April 17 to Mar18

Demand	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Indexed		100	104	108	108
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Indexed		100	114	108	110
Imports from					
China	MT	4,356	1,930	2205	2969
Other Countries	MT	79	115	30	65
Total Demand	MT	48,251	50,295	49,603	50,835

102. The Authority notes that the demand has shown increase over the injury period, even though it had marginally declined in 2016-17 as compared to the preceding year. The demand increased once again in the period of investigation as compared to both the preceding year and base year.

(ii) Volume Effect of Dumped Imports and impact on Domestic Industry: Import volume and Market Share.

103. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The table below summarizes the factual position with regard to import volumes and market share:-

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI	POST POI 2018-19
China	MT	4,356	1,930	2205	2,969	981
Other Countries	MT	79	115	30	65	43
Total imports	MT	4,434	2,045	2235	3034	1024
Market Share in Demand						-
Sale of Domestic Industry	%	***	***	***	***	-
Sale of other Indian Producers	%	***	***	***	***	-
Import from subject country	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%	-
Import from other countries	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%	-
Total Demand	%	100	100	100	100	-

104. It is seen that the import volume declined till 2015-16 and increased thereafter. Further, the imports have decreased from 2969 MT in POI to 981 MT in post POI. Also, the market share in demand of the domestic industry has remained more or less constant.

(iii) Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

105. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

Price Undercutting

Particulars	Unit	POI
Landed price of imports from China PR	Rs./Kg	250.06
Net Sales Realization	Rs./Kg	***
Price undercutting	Rs./Kg	(***)
Price undercutting	%	(***)
Range		(0-10)

From the above, the Authority notes that there is no price undercutting.

106. The domestic industry submitted and opposing interested parties have not disputed that the entirety of the imports were made under advance license and therefore neither customs duty nor ADD was paid on these imports.

b. Price Suppression/ Depression

107. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:-

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales	Rs. /Kg	***	***	***	***
Trend		100	89	87	99
Selling price	Rs. /Kg	***	***	***	***
Trend		100	93	89	103
Landed price of imports	Rs./Kg	265	266	238	250
Trend		100	102	87	94

108. The Authority notes that whereas the selling price has increased in the POI as compared to the base year, the cost of sales has marginally declined in POI. The landed value of imports from subject country has increased in POI as compared to the previous year. The Authority notes that the domestic industry increased its selling price in proportion to increase in cost of sales throughout the injury period. Therefore, there is no price suppression or depression.

(iv) Economic Parameters of the Domestic Industry

109. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

110. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:-

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

111. Production, sales, capacity & capacity utilization details are as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	111	126
Capacity utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	111	126
Domestic Sales for PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	113	116	117

112. From the above information, the Authority notes the following:-

- Capacity of the domestic industry has remained constant over the period.
- The production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry has increased over the injury period.

b) Demand

Demand	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Indexed		100	104	108	108
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Indexed		100	114	108	110
Imports from					
China	MT	4,356	1,930	2205	2969
Others	MT	79	115	30	65
Total Demand	MT	48,251	50,295	49,603	50,835

113. From the above information, the authority notes that the sales of the DI and other producers have increased from the base year.

c) Market Share in Demand

114. The details of market share of the Domestic Industry in demand are given in table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sale of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sale of other Indian Producers	%	***	***	***	***
Import from subject country	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
Import from other countries	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
Total Demand	%	100	100	100	100

115. It is seen that the market share of Domestic Industry has marginally increased over the injury period.

a. Profitability, return on investment and cash profits

116. Performance of the Domestic Industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows: -

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profit/(Loss)	Rs./ Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	375	225	325
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	240	165	255
Return on Capital Employed- NFA	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	173	90	136

117. It is seen from the above table that the profitability, cash profits and return on investments have increased in the POI when compared to the base year.

a. Inventories

118. Inventories with the Domestic Industry are as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	125	130

119. It is noted that the average inventory level of the subject goods has shown an increasing trend.

b. Employment, Productivity and Wages

120. Performance of the Domestic Industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	118	119
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	138	168
Productivity/person/Day	Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	94	94	106

121. It is seen from the above that the number of employees, wages and productivity during POI have increased as compared to the base year.

I. Magnitude of Injury and injury margin

122. The Non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under.

S.N.	Particular	UOM	China (POI)
1	Import Volume	MT	2969
2	Non Injurious Price	Rs/KG	***
3	Landed Price	Rs/KG	250
4	Injury Margin	Rs/KG	***
5	Injury Margin	%	***
6	Injury Margin Range		0-(10)

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

123. As this is a Sunset Review investigation and the authority now examines the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were allowed to expire.

J.1 Submissions by the Domestic Industry

124. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

i. A perusal of Article 11.1 of AD Agreement and Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, clearly suggests that the main intent behind the legislation of Sunset Review investigation is to examine: -

(a) Whether the dumping continued and if so, whether it is likely to continue;

- (b) In case where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti-dumping duties;
 - (c) Whether the Domestic Industry continued to suffer injury; and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
 - (d) In case where the Domestic Industry has not suffered continued injury, whether injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.
- ii. The original investigation and the subsequent Sunset Review investigations also established the existence of significant dumping. The dumping margin in the previous as well as the first SSR was quite high.
 - iii. There is a long history of dumping of subject goods from China in domestic market as well as in other countries such as South Africa and Indonesia.
 - iv. The continued dumping was only reduced after the last concluded sunset review investigation. Prior to that, the domestic industry was suffering continued injury on account of significant dumped imports, as stated by the Authority in the final findings earlier notified in the review cases.
 - v. The significant level of these imports only started declining since 2015-16. However, it is pertinent to note that the domestic industry is still healing from the past injurious effects of dumping and thus is in a vulnerable state. Cessation of anti-dumping duties is likely to cause intensified injury to the domestic industry.
 - vi. It would appear that the domestic industry has enjoyed antidumping duty protection for the last 15 years, the fact is that the domestic industry has been effectively protected for only last five years. The Chinese producers continued dumping and the same caused injury to the domestic industry for one decade, despite the ADD being in force.
 - vii. The change in the form of duty from benchmark to fixed quantum has led to reduction in imports. Cessation of antidumping duty is likely to increase the imports as significant surplus capacities are available with the producers. The decline in the imports is because of existence of ADD.
 - viii. Due to continuous dumping, several plants producing the PRODUCT UNDER CONSIDERATION have been closed down in the country namely:-
 - M/s Triton Laboratories Ltd.
 - M/s Vamsi Labs Ltd.
 - M/s Srinivasa Agro Industries & Drugs Ltd.
 - M/s Pan Drug
 - M/s Alpha Drug
 - M/s Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.
 - M/s Thexa Pharma Pvt. Ltd.
 - M/s Vani Pharma Labs Ltd.
 - Rohini Chemical
 - Fortune Chemical
 - Dinesh Pharmaceutical
 - Dr. Jain's Company
 - Saboo Medichem
 - ix. The production of product under consideration is quite limited globally. About 86% of global production is in India and China. 62% of the production is in China alone, while India commands 24%. Thus, any sickness in this industry would leave the global demand at the mercy of the Chinese producers.
 - x. The questionnaire responses filed by the exporters, establish that there is import of subject goods from subject country at dumped price.
 - xi. The domestic industry in the present scenario is still reeling from the adverse effects of the dumping and has shown marginal growth in terms of its economic parameters. The same growth would be reversed if the Anti-dumping duty is ceased by the Authority.
 - xii. The only reason the domestic industry has not suffered further deterioration in its performance is that the volume of imports was low due to the duties in force. However, the producers in the subject country have significant idle

capacities, which are sufficient to meet the entire demand in India. In the event of cessation of duty, the exports are likely to utilize these unutilized capacities and flood the Indian market.

- xiii. The foreign producers are export oriented, in as much as their capacities are far more than the domestic demand in the subject country. The production of the subject goods in subject country is in the range of 1 lac MT, as against 2.21 lac MT capacities; whereas the domestic demand for the product in China is far lower nearly 20,000 MT. This clearly shows that the exporters have built up capacities in excess of the demand in the subject country out of 1 lac MT production, about 80% are meant for exports.
- xiv. The exporters have not only been dumping in India, but also in other countries. Further, the prices at which the goods have been supplied to these countries are lower than the non-injurious price. It is therefore, reasonable to conclude that the exporters are likely to sell at dumped and injurious prices in India as well in case the duty is revoked.
- xv. The export price from subject country to various countries globally are far lower than the export price to India in respect of significant proportion of exports from subject country to various countries globally. The dumping margin and injury margin in these third countries exports are higher than the dumping margin and injury margin in respect of exports to India.
- xvi. Since India is a more price attractive market as compared to third countries, the exporters would prefer to divert their goods from other countries to India in case of revocation of duty, in order to increase their profits and capture the market. Considering that the exporters have no commitments in these third country markets and the sole criteria for them to price their product is price received by them.
- xvii. Decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.

J.2 Submission of exporters

125. There is no likelihood of recurrence of injury as per Article 9A (5) of the Customs and Tariffs Act.
 - i. The petitioners have not given the details of excessive capacity available with the Chinese producers and their likelihood of being exported to India, the petitioners have failed to make out a case of likelihood of dumping.
 - ii. This clearly indicates that there is no likelihood of injury to the domestic industry in the current investigation and the present investigation deserves termination.

J.3 Examination by the Authority

126. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Anti-dumping Rules.
127. The Authority has noted the details submitted by the domestic industry regarding exports of China to third countries as per China customs which shows that 28.6% volume of exports to third countries are at a price lower than price at which China exports to India and 64 % of the volume of exports to third countries are at a price above than price at which China exports to India.
128. The Authority has taken into consideration the submissions made by the domestic industry and the evidence presented in support of their submissions. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury under following heads:
 - a. A significant rate of increase importation; of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.

Each of the above parameters is accordingly analyzed in view of information placed on record by the interested parties.

(a) A significant rate of increase importation; of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

- **Volume of imports during the injury period and post POI**

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI 2017-18	POST POI 2018-19
China	MT	4,356	1,930	2205	2969	981
Others	MT	79	115	30	65	43
Total imports	MT	4,434	2,045	2,235	3,034	1024

**April 17 to Mar18*

129. The Authority notes that there has been decline in the volume of imports from subject country from 2969 MT in the POI to 981 MT in the post POI.

130. It is also seen that there is a decline in the volume of imports in POI and post POI as compared to the base year.

(b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

131. Total exports to India was 2969 MT during POI out of which 2543 MT was from the cooperative exporters.

132. The Authority noted the submission of the DI regarding the existing surplus capacities, capacity addition, if any, with the responding exporters, possibility of trade diversion from third countries to India, freely disposable production capacities with the responding exporters. The analysis shows as follows:-

a. Capacity, production, surplus capacities, exports to India and rest of the world, volume of exports to India.

Name of Producer	Units	Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.	Total
Capacity	MT	***	***	***	***
Production (POI)	MT	***	***	***	***
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
Domestic Consumption	MT	***	***	***	***
Exports to India	MT	***	***	***	***
Exports to ROW	MT	***	***	***	***
Total Exports	MT	***	***	***	***
% Exports Orientation	Range %	35	54	39	39

b. After analysis of the capacities of the cooperative exporters, the Authority notes the capacities of non-cooperative exporters/producers as per the data submitted by the petitioner and the information available in public domain which is as under:-

S. No.	Producers in China	Capacity (MT per annum)
1.	Anhui BBKA Likang Pharmaceutical	10,000
2.	Changshu Huagang Pharmaceutical	8000
3.	Jiangsu World kindly Pharmaceutical	10000
4.	Wenzhou Pharmaceuticals factory	6,000
5.	Jiangsu Guoheng Pharma chemicals Co., Ltd.	2,500

6.	Runqi trading Co., Ltd	12,000
7.	Shanghai Bailion Chemicals Co., Ltd	50,000
8.	Lianoyuan City Baikang Pharmaceutical	500
9.	Total capacity of non-co-operative entities	99,000
10.	Total capacity of cooperative producers	75,000
11.	Total capacity of China PR	174,000
12.	Indian demand	50,835

C. It is observed from the analysis of the cooperating producers that the trading companies do not have their own production facilities and they quote the capacity of the producers on their websites.

d. Considering the capacity utilisation and export orientation of the responding producers and evidence provided by the domestic industry, it is evident that there are not much surplus capacities in China of cooperative exporters which represent 85% of the total export to India and the export orientation of the cooperative producers is 39% of production.

(C) Inventories of the article being investigated

133. The questionnaire response filed by the Chinese producer's shows that level of inventories with the cooperative producers/ exporters is not quite significant in comparison to Indian demand as can be seen from the table below.

Producer	Units	2015	2016	2017	POI
M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	MT	***	***	***	***
Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	MT	***	***	***	***
Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
Total	MT	***	***	***	***
Indian Demand	MT	48,251	50,295	49,603	50,835

(D) Price attractiveness of Indian market

134. The export price to India and the quantities exported to India in comparison to other countries has been mentioned in the table below :-

S.NO.	Country	Quantity (kg)	Value USD	Price USD/kg
1.	Sweden (SE)	200	2135	10.68
2.	Switzerland (CH)	200	1960	9.80
3.	Puerto Rico (PR)	76000	722540	9.51
4.	Korea DPR (KP)	7294	59996	8.23
5.	Sengal (SN)	37200	275722	7.41
6.	New Zealand (NZ)	36700	265774	7.24
7.	Spain (ES)	726182	4731798	6.52
8.	Honduras (HN)	2700	17247	6.39
9.	Cyprus (CY)	1510	9597	6.36
10.	Portugal (PT)	11000	69148	6.29
11.	Oman (OM)	75000	465278	6.20
12.	Australia (AU)	194061	1165226	6.00
13.	Jamaica (JM)	550	3184	5.79
14.	Tunisia (TN)	97850	564678	5.77

15.	Croatia Rep (HR)	18000	103048	5.72
16.	Kazakhstan (KZ)	3000	16692	5.56
17.	Algeria (DZ)	371325	2043715	5.50
18.	Albania (AL)	255	1403	5.50
19.	Uruguay (UY)	15075	81821	5.43
20.	Romania (RO)	113635	610836	5.38
21.	Kirghizia	3150	16881	5.36
22.	Korea Rep (KR)	917072	4800689	5.23
23.	Argentina (AR)	131676	669468	5.08
24.	Greece (GR)	26400	131646	4.99
25.	Sri Lanka (LK)	22500	111160	4.94
26.	Laos PDR (LA)	1025	5060	4.94
27.	Italy (IT)	410574	2024742	4.93
28.	Japan (JP)	673277	3290755	4.89
29.	United States (US)	1329487	6478959	4.87
30.	Mongolia (MN)	13325	63689	4.78
31.	Panama (PA)	65688	311056	4.74
32.	Costa Rica (CR)	15500	73335	4.73
33.	Moldavia (MD)	200	940	4.70
34.	Saudi Arabia (SA)	57050	268095	4.70
35.	Germany (DE)	783030	3673146	4.69
36.	Guyana (GY)	500	2344	4.69
37.	Morocco (MA)	192450	900783	4.68
38.	Finland (FI)	36000	168368	4.68
39.	Poland (PL)	39895	185434	4.65
40.	Paraguay (PY)	31550	146388	4.64
41.	Hungary (HU)	317800	1469842	4.63
42.	France (FR)	2723382	12530613	4.60
43.	Haiti (HT)	500	2300	4.60
44.	Slovenia Rep (SI)	70950	326288	4.60
45.	Ireland (IE)	409446	1851772	4.52
46.	Lebanon (LB)	20300	91677	4.52
47.	Canada (CA)	322933	1456263	4.51
48.	Israel (IL)	12500	56197	4.50
49.	Kampuchea	192350	864025	4.49
50.	Hong Kong (HK)	93600	418493	4.47
51.	Bulgaria (BG)	14000	62440	4.46
52.	Czech Rep	150000	664200	4.43
53.	Macedonia Rep (MK)	20000	88500	4.43

54.	United Kingdom (GB)	321400	1418800	4.41
55.	Denmark (DK)	10750	47285	4.40
56.	Norway (NO)	57000	249351	4.37
57.	Cote d Lvoire	2200	9622	4.37
58.	Georgia (GE)	1500	6530	4.35
59.	Sudan (SD)	1050	4528	4.31
60.	Ecuador (EC)	52050	222496	4.27
61.	Zimbabwe	48500	205666	4.24
62.	Venezuela (VE)	31950	133412	4.18
63.	Jordan (JO)	163955	683314	4.17
64.	Ukraine (UA)	31010	129033	4.16
65.	Mexico (MX)	228035	942760	4.13
66.	Uzbekstan (UZ)	97500	402696	4.13
67.	Rep Yemen	7005	28702	4.10
68.	Netherlands (NL)	642800	2612640	4.06
69.	Byelorussia	43768	176654	4.04
70.	Philippines (PH)	420125	1680716	4.00
71.	Egypt (EG)	1077390	4289120	3.98
72.	Pakistan (PK)	537515	2130457	3.96
73.	Belgium (BE)	401000	1574454	3.93
74.	Turkey (TR)	754759	2947147	3.90
75.	Guatemala (GT)	128800	501363	3.89
76.	Brazil (BR)	1443432	5569782	3.86
77.	Malaysia (MY)	298155	1148139	3.85
78.	Singapore (SG)	153250	590125	3.85
79.	Ethiopia (ET)	49625	189732	3.82
80.	Colombia (CO)	237661	907214	3.82
81.	Peru (PE)	209575	798631	3.81
82.	Latvia (LV)	36000	136184	3.78
83.	Chile (CL)	89390	338000	3.78
84.	Nigeria (NG)	2454182	9192619	3.75
85.	Mali (ML)	17800	66067	3.71
86.	Ghana (GH)	429510	1586019	3.69
87.	Cameroon (CM)	4025	14841	3.69
88.	Myanmar (MM)	69735	256063	3.67
89.	Nicaragua (NI)	8300	30433	3.67
90.	El Salvador (SV)	55400	202809	3.66
91.	Thailand (TH)	2475900	9061183	3.66
92.	Bolivia (BO)	11300	41351	3.66

93.	Vietnam (VN)	2763850	10096528	3.65
94.	Bangladesh (BD)	273000	995763	3.65
95.	Dominican Rep (DO)	4850	17586	3.63
96.	Djibouti (DJ)	13675	49564	3.62
97.	Taiwan (TW)	365950	1325995	3.62
98.	Georgia (GE)	1500	6530	4.35
99.	Sudan (SD)	1050	4528	4.31
100.	Ecuador (EC)	52050	222496	4.27
101.	Zimbabwe	48500	205666	4.24
102.	Venezuela (VE)	31950	133412	4.18
103.	Jordan (JO)	163955	683314	4.17
104.	Ukraine (UA)	31010	129033	4.16
105.	Mexico (MX)	228035	942760	4.13
106.	Uzbekistan (UZ)	97500	402696	4.13
107.	Rep Yemen	7005	28702	4.10
108.	Netherlands (NL)	642800	2612640	4.06
109.	Byelorussia	43768	176654	4.04
110.	Philippines (PH)	420125	1680716	4.00
111.	Egypt (EG)	1077390	4289120	3.98
112.	Pakistan (PK)	537515	2130457	3.96
113.	Belgium (BE)	401000	1574454	3.93
114.	Turkey (TR)	754759	2947147	3.90
115.	Guatemala (GT)	128800	501363	3.89
116.	Brazil (BR)	1443432	5569782	3.86
117.	Malaysia (MY)	298155	1148139	3.85
118.	Singapore (SG)	153250	590125	3.85
119.	Ethiopia (ET)	49625	189732	3.82
120.	Colombia (CO)	237661	907214	3.82
121.	Peru (PE)	209575	798631	3.81
122.	Latvia (LV)	36000	136184	3.78
123.	Chile (CL)	89390	338000	3.78
124.	Nigeria (NG)	2454182	9192619	3.75
125.	Mali (ML)	17800	66067	3.71
126.	Ghana (GH)	429510	1586019	3.69
127.	Cameroon (CM)	4025	14841	3.69
128.	Myanmar (MM)	69735	256063	3.67
129.	Nicaragua (NI)	8300	30433	3.67
130.	El Salvador (SV)	55400	202809	3.66
131.	Thailand (TH)	2475900	9061183	3.66

132.	Bolivia (BO)	11300	41351	3.66
133.	Vietnam (VN)	2763850	10096528	3.65
134.	Bangladesh (BD)	273000	995763	3.65
135.	Dominican Rep (DO)	4850	17586	3.65
136.	Djibouti (DJ)	13675	49564	3.62
137.	Taiwan (TW)	365950	1325995	3.62
138.	India (IN)	3080621	11128592	3.61
139.	Congo, DR	89300	322233	3.61
140.	Cuba (CU)	16850	60660	3.60
141.	Kenya (KE)	941170	3385483	3.60
142.	Mauritius (MU)	4000	14280	3.57
143.	Indonesia (ID)	7667860	27314431	3.56
144.	S. Africa (ZA)	175600	624786	3.56
145.	Iraq (IQ)	191450	677055	3.54
146.	Zambia (ZM)	119025	419477	3.52
147.	Russia (RU)	2015515	7039254	3.49
148.	Iran (IR)	81750	284072	3.47
149.	Syrian (SY)	289800	1005553	3.47
150.	Benin (BJ)	39500	134850	3.41
151.	Mozambique (MZ)	68000	231030	3.40
152.	United Arab Emirates (AE)	206600	686013	3.32
153.	Tanzania (TZ)	268000	883641	3.30
154.	Lithuania (LT)	42150	138818	3.29

Source: China Custom

135. The Authority notes that 28.6 % total volume of exports to third countries is at a price lower than the price at which China exports to India. Whereas 64.18 % of the total exports are exported above the price at which China exports the subject goods to India.

(E) Export Orientation of China PR

136. As per the data of China Customs and other evidence filed by the Domestic Industry, the Authority notes that the cooperative producers in China are export oriented to the extent of 39%. Therefore, in the event of cessation of ADD, probability is not very high that the exporters/producers would resort to dumping of subject goods to India.

K. CAUSAL LINK AND NON ATTRIBUTION ANALYSIS OF OTHER KNOWN FACTORS

137. Having examined the existence of continued dumping, volume and price effects of dumped imports on the prices of the Domestic Industry, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined herein below by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed injury to the Domestic Industry.

a. Volume and price of imports from third country:

138. Statement of imports from countries other than the subject country shows that the imports of subject goods from other countries are entering at below de minimis level. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry

b. Contraction in Demand and / or Changes in Pattern of Consumption

139. Overall demand for the subject goods has shown positive growth during the injury period. It is also noted that no significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the authority, nor any interested party has made any submission in this regard.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

140. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country. The Domestic Industry competes among one another and at the same time competes with the imports of the subject goods.

d. Development in technology:

141. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

e. Export performance of the Domestic Industry:

142. Domestic Industry has exported the subject goods. However, the price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, export performance would not have affected the injury analysis made by the Authority in this statement.

f. Performance of other products:

143. Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over the reported performance of the subject product as the Authority has examined the performance of the subject goods only.

POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Submissions by the Domestic Industry

144. It is submitted by the Authority that the last date and time for the submission of the post disclosure statement was 30th September 2019 at 6.00 PM however the soft copy of the comments was received at 30th September 2019 at 6.55 PM. The hard copy of the same was received on 01.10.2019 at 05.00PM. Despite their late submissions the authority has taken a lenient view and has considered their responses. The post-disclosure comments made by the interested parties are mostly reiterations. However, the comments considered relevant by the Authority are addressed.
145. The DI in their preliminary submissions request the disclosure of the copy of communication sent by the authority and copy of the replies filed by the interested parties. The DI requested to make available copy of all communications sent via mail or letter to the opposing interested parties, including rejoinders and verification report prepared by the authority.
146. The DI submits that the interpretation and conclusions drawn from the same information are different in the previous disclosure statement/ Final Findings and present disclosure statement.
147. An analysis of the transaction wise data of the cooperative producers with their respective exporters, so as to arrive at dumped and injurious imports of the cooperative producers was carried out in the previous disclosure statement and final finding. The present disclosure contains no such analysis. The deletion of analysis has rendered the present disclosure statement incomplete. Thus the final findings shall be based on the incomplete establishment of essential facts under consideration.
148. With regard to the surplus capacities in China the situation where the Chinese producers are exporting 39% of their production it cannot be concluded that there is not much surplus capacities in China.
149. The capacity utilization analysis has been restricted to the responding exporters, it does not take into account significant volume of exports that are accounted by those producers who have not preferred cooperation. The fact that responding producers' exports constitute 85% of total exports to India is immaterial in deciding whether Chinese producers hold surplus capacities and are export oriented. The fact that a significant proportion of capacity /production is accounted by the non-cooperating producers should be linked to Chinas global exports and third country exports by responding exporters.
150. In the present disclosure statement it is stated that the questionnaire response filed by the Chinese producer shows that the level of inventories with the cooperative producers is not quite significant in comparison to Indian demand however the previous disclosure statement showed rising inventories with the foreign producers. In such a scenario the petitioners are unable to understand the basis of the statement that the inventories with the exporters is not high.
151. In the previous disclosure statement/Final findings The analysis of the Chinese PR Custom data with regard to export from China PR indicate that with the revocation of ADD, the Indian prices would be attractive for the Chinese producers/Exporters however the Designated Authority deleted the same while issuing the present disclosure statement.

152. In the previous final Finding/disclosure the designated authority noted that the producers in China are oriented towards exports globally whereas in the present disclosure the Authority notes that the producers in China are export oriented to the extent of 39%. Thus this renders the present disclosure incomplete.
153. The DI stated that from the perusal of the disclosure statement it is very clear that the Designated Authority has deleted the dumped and injurious volume analysis done for the participating exporter/ producer without any reason. The present investigation admittedly concerns an examination of likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. The disclosure statement clearly shows positive dumping margin and therefore likelihood of dumping is well established. DI states that analysis based on weighted averages can be highly misleading. For these reasons, the authority has examined behavior of foreign producers by considering individual export transactions in the past in several investigations. Further, the analysis has been carried out by considering exports to India and exports to third countries. While responding producers have given data with regard to export to India and authority is in a position to undertake similar analysis, as far as exports to third countries are concerned, the exporters are non-cooperative. Thus, as far as exports to India is concerned, since relevant information is on record, petitioners submit that the same is required to be examined considering invoice by invoice exports to India. In a situation where significant proportion of exports to India are below normal value, the very fact that some exports to India are above normal value does not imply no likelihood of dumping in the event of cessation of ADD. On the contrary, significant exports to India at a price below normal value clearly establishes likelihood of dumping in the event of cessation of ADD.
154. As far as exports to third countries are concerned, since exporters have preferred non-cooperation and have withheld relevant information with regard to individual export transactions to third countries, the authority is requested to apply adverse facts to the exporters (and not against domestic industry) and hold that the same clearly establishes likelihood of dumping. Further, the authority is requested to consider the information provided by the petitioners which shows a significant proportion of exports at a price below normal value. As per the DI's data, 15610 MT has been exported from China to various countries at a price below normal value. As against this volume of exports below normal value, the Indian demand is only 50000 MT. Further, as against 15610 MT exports to third countries at a price below normal value, 4000 MT was exported at a price below selling price prevailing in India. Thus, in a situation where exporters were selling 15610 MT to third countries at dumping price and at a price below selling price in India, it follows that these exporters would be in a position (and in fact will wish) to divert these exports to India at a dumping price. Thus, the petitioner (DI) request the authority to kindly consider a volume of 15610 MT for a purpose of establishing likelihood of dumping and injury.
155. The DI states that in the present disclosure statement the designated authority has noted the capacities of responding producers but has ignored the capacity which is available with the non-cooperative Chinese producers. The DI request the designated authority to not to reward their non-cooperation by presuming that they do not have significant surplus capacities. Particularly when the Designated Authority has information with regard to (a) exports from China by various companies, (b) exports from China by responding producers.
156. The present disclosure statement does not consider the following submission of the petitioners:
157. The exporters questionnaire filed by responding exporter/producer namely M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co. Ltd, Zhejiang Kangle Pharmaceuticals Co. Ltd, M/s AHA International Co. Ltd, Zhejiang Chemical Import & export cooperation and China Sinopharm International Corporation are deficient in nature and none of them have filed the exporter Questionnaire Responses (Part 2), which seeks information from exporters on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, Inventories etc. there details are indicative of the Likelihood behavior of the exporters are required to be submitted to the authority in the sunset Review Investigation.
158. The exporter's questionnaire response states that there is a decline in the capacity utilization of the exporter giving rise to the idle capacity. Domestic sales of exporter has come down and sales to India has increased.
159. Imports have increased in the absolute term in the Period of investigation (POI) as compared to the preceding two years. The landed value of imports is below the cost of production for the subject goods and imports are undercutting the prices of the domestic industry. The cessation of duty will lead to increase in imports in absolute terms as well as in relation to production and its return on capital employment would become negative.
160. The domestic consumption of the product has decline in China however the capacities have not been proportionately reduced which proves a threat for industries outside China.
161. The API sector needs protection from imports and Indian Government commits to revive the API sector in India. Katoch Committee Report dated 24 September, 2015 states that a long term strategy is required for strengthening API sector in which role of Ministry of Commerce as well as other regulatory authorities is a must, it must also involve liberal use of Antidumping measures.
162. The effective imposition of duty in the previous Sunset Review investigations, the various producers have made fresh investment in the country. A total of about Rs.40.86 Crores and capacities by 20000 MT has been invested in

this industry after the last protection. Cessation of anti- dumping duty will cause injury to the domestic industry and these investment will be jeopardized.

163. As regards the price attractiveness, DI states that any analysis on the basis of weighted average is at the least highly misleading. Every sales transaction is made independently by every manufacturer and on standalone basis. If there are significant exports made to third countries at lower prices, there is no submission/justification by these interested parties why those sales would not be diverted to Indian market. The responding exporters have neither shown any compulsion nor any other reason for selling at lower prices to third countries and factors which would prevent them from diverting those low priced sales to India. The Chinese producers do not appear to be charitable institutions and are business organizations whose objective is to maximize the profits.
164. It is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price. The Designated Authority is, therefore, requested to compute the weighted average normal value and compare the same with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same are required to be excluded for determination of dumping margin
165. The legal provisions does not refer to surplus capacity. The Authority may examine “freely disposable production capacity”, having regard to long term commitments made by the exporters and capacities dedicated by them for domestic and third countries markets. The domestic industry is unaware of any long term commitments made by these exporters for supplies in third countries. Nor the responding producers have brought any such evidence on record. Such being the case, unutilized capacities and all exports, at the minimum, constitute freely disposable production capacities. And the evidence adduced by the petitioning domestic industry in this regard in the petition and written statement establishes it beyond a shadow of doubt that the imports from the subject country are likely to cause injury to the petitioning domestic industry.
166. The DI contends that the determination of export price that the price at which the goods were exported to India alone cannot become basis for the determination.
167. There is a difference in the price at which the producer/exporters are exporting to India. The DI states that if the price at which the responding producers have directly exported the product and the price at which such producers have given the material to the traders for eventual export to India are compared, it will be seen that the producers have sold the material to Chinese trader for eventual export to India at a price materially lower than the prices at which the traders have sold the product in the Indian market. Further, the producers have also directly invoiced the product to Indian market at much higher prices.
168. The DI reiterates the fact that the Designated authority should not consider the Chinese producers cooperative as the exporters questionnaire filed by the Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co Ltd, M/s A.H.A International Co. Ltd. Zhejiang Chemicals import and export cooperation and China Sinopharm International Cooperation are incomplete, as none of these parties have filed response to the exporter Questionnaire Response (Part 2) which seeks information from the exporters on invoice wise exports to third countries. This information is very important for the likelihood determination in a Sun set review investigation.
169. The statement helps to determine the dumping margin and injury margin in individual export transaction to third countries. The DI requests the designated authority to consider the responses filed by the exporter/producer as defective and to be treated as non-cooperative.

L.2 Submission by the Exporter

170. The exporter has no comments on the disclosure statement.

L.3 Examination by the Authority

171. As regards the submission regarding the disclosure of the copy of the communications sent via email or letter to the opposing interested parties it is stated that all essential facts under Rule 16 of Anti-dumping Rules have been disclosed. All the Non-confidential version of the communication including emails sent to the opposing party are kept in the public file.
172. It is submitted that our present disclosure statement is issued as per the existing trade practices and rules. Dumping and injury analysis has been carried out as per rules and past practices of the authority. In every case dumping margin is worked out on the basis of weighted average of all the transactions as per rules.
173. The analysis of the China PR custom data with regard to export from China PR indicate that as 64% of the total exports are exported above the price at which China exports the subject goods to India and therefore Indian market does not seem to be price attractive in comparison to other countries.
174. As regards the examination of surplus capacities of non-cooperative exporters is concerned it is noted by the authority that the information on surplus capacities available with non-cooperative exporters/producers is on the basis of the data submitted by the domestic industry and the information available in public domain. It is further

observed by the authority that traders in China PR quote the capacities of the producers on their websites and they do not have their own production facilities and therefore the capacities mentioned at their websites is misleading. However, the authority does not deny the surplus capacities available with Chinese producers (including non-cooperative producers). Even if there are surplus capacities available with China PR the authority is of the view that in the event of cessation of duty there is a remote possibility of dumping as the Indian market is not price attractive in comparison to other countries.

175. Details of cooperative exporters regarding their capacity, capacity utilization, domestic sales and inventories have been provided in their exporters' response (NCV) in indexed form and the analysis has been done under the relevant heads.
176. The analysis regarding the volume of imports, landed price and related parameters has been done under the relevant heads which states that there has been a decline in the volume of imports from subject country from 2969 MT in the POI to 981 MT in the post POI period i.e. April 2018 to March 2019. As regards the landed price being lower than the cost of production for the subject goods, it is observed that cost of sales throughout the injury period has been much lower in comparison to landed price of the PUC so the contention of domestic industry is not agreed upon in this context.
177. As regards the stance of Government of India as expressed in documents such as Katoch Committee report, 145th Parliamentary report and Office Memorandum dated 18th April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, the Authority notes that the present investigation is conducted as per Rules, facts of the case and past practices of the Authority.
178. As regards the contention regarding global production being bifurcated between China and India and the state of present domestic industry, the Authority notes that as per its injury analysis, the production of domestic industry is sufficient to cater to the Indian demand.
179. The analysis of the price attractiveness by the Authority does not position India as price attractive for Chinese Exports so far as subject goods are concerned.
180. Other post disclosures submissions made by the domestic industry have already been addressed under the relevant headings.

L. CONCLUSIONS

181. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding, the Authority concludes that:-
1. Evidence on record do not indicate that the dumped imports from China PR will lead to injury to Domestic Industry.
 2. Import of the subject goods from China PR has remained at insignificant level throughout the injury period and decreased in the post POI period.
 3. The domestic industry has shown improvement in terms of all injury parameters and there is no injury to the Domestic industry. Furthermore, the production of subject goods by domestic industry is sufficient to cater to Indian demand.
 4. The analysis of the price attractiveness by the Authority does not position India as price attractive for Chinese Exports so far as subject goods are concerned and therefore there is very less likelihood that exports from China PR would be diverted to India in case ADD ceases.
 5. The ADD was in force since September' 2001 and the condition of domestic industry has improved. Therefore, the ADD has served its intended purpose.

M. RECOMMENDATION

182. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to domestic industry, exporters, importers, users and other interested parties to provide relevant information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link and likelihood of dumping post cessation of ADD in force in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Act and Rules, the Authority holds that the expiry of the said anti-dumping duty will not lead to injury to the domestic industry due to reasons and/or analysis given above. Therefore, the Authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General